मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
हर खबर निष्पक्षता के साथ
मुंबई
वर्ष: 8 अंक 315
शुक्रवार, 05 जून 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, खरगे और पवन खेड़ा कर्नाटक से मैदान में

नई दिल्ली, 04 जून। आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी बिसात बिछा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विभिन्न राज्यों से पार्टी उम्मीदवारों की सूची पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इस सूची में पार्टी के प्रखर प्रवक्ताओं से लेकर अनुभवी रणनीतिकारों तक को जगह दी गई है, जिससे पार्टी ने एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि सदन में सरकार को घेरने के लिए वह अपने सबसे अनुभवी चेहरों को आगे ला रही है।

कांग्रेस ने कर्नाटक से पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा को मैदान में उतारकर बड़ा संकेत दिया है। उनके साथ ही मंसूर अली खान को भी कर्नाटक से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें राहुल गांधी की कोर टीम का भरोसेमंद माना जाता है।

राजस्थान: यहां से नीरज डांगी पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है।

तमिलनाडु: रणनीतिक विभाग में अहम भूमिका निभाने वाले प्रवीण चक्रवर्ती को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है।

झारखंड: संगठन में सक्रिय रहने वाले प्रणव झा को झारखंड से राज्यसभा भेजने की तैयारी है।

सूची में खरगे का नाम भी शामिल

हैरान करने वाली बात यह है कि जारी की गई सूची में सबसे ऊपर स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम भी उम्मीदवारों के रूप में शामिल है। हालांकि वे वर्तमान में सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन सूची में उनका नाम होना उनके नेतृत्व और अनुभव पर पार्टी के अटूट विश्वास को दशार्ता है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवीण चक्रवर्ती और पवन खेड़ा जैसे चेहरों को चुनकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वह राज्यसभा में डेटा, तथ्यों और आक्रामक भाषणबाजी के दम पर सत्ता पक्ष को चुनौती देने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि इन दिग्गजों की एंट्री से उच्च सदन के भीतर सियासी पारा कितना चढ़ता है।

टीएमसी में बड़ी बगावत, मेयर का इस्तीफा

कोलकता, 04 जून। हाल ही में संपन्न हुए राज्य चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हाथों करारी हार के कुछ दिनों बाद, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पश्चिम बंगाल में सत्ता खोने के बाद अपने विधायी रैंकों में विद्रोह से जूझ रही है। स्पीकर द्वारा 58 बागी टीएमसी विधायकों को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मान्यता देने के बाद, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। अब पार्टी को अपने शहरी राजनीतिक ढांचे में एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रमुख महापौर पदों पर आसीन वरिष्ठ नेताओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

स्पीकर रथेंद्र नाथ बोस ने विधायक ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व में 58 बागी टीएमसी विधायकों को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी। बागी विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया है और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भूमिका को खुले तौर पर चुनौती दी है। इस पृष्ठभूमि में, टीएमसी के सबसे प्रभावशाली शहरी नेताओं में से एक, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं, जिनका कथित इस्तीफा अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस सप्ताह की शुरूआत में, टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने घोषणा की कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हकीम के इस्तीफे के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

घोष के हवाले से बताया गया कि उस समय उनसे इस्तीफा न देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, उन्होंने आज ममता बनर्जी से फिर से इस्तीफा देने की अनुमति मांगी, जिसके बाद ममता बनर्जी मान गईं। हालांकि, समाचार एजेंसी के अनुसार, इस्तीफा अभी तक औपचारिक रूप से कोलकाता नगर निगम (केएमसी) तक नहीं पहुंचा है।

केएमसी अध्यक्ष माला रॉय ने कहा, मुझे अभी तक फिरहाद हकीम का इस्तीफा नहीं मिला है। नियमों के अनुसार, यदि महापौर इस्तीफा देना चाहते हैं, तो उन्हें इसे मुझे सौंपना होगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नबन्ना में हुई एक प्रशासनिक बैठक में हकीम की उपस्थिति के बाद अनिश्चितता और बढ़ गई, जिससे कथित तौर पर टीएमसी नेतृत्व के कुछ वर्गों में असहमति पैदा हो गई।

कल्याण फ्लोर मिल एसोसिएशन ने मुख्य अभियंता का किया सम्मान

कल्याण। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, कल्याण के मुख्य अभियंता चंद्रमणि मिश्रा का कल्याण फ्लोर मिल एसोसिएशन की ओर से सम्मान किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन रविकांत थोर, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रधारी यादव, महासचिव जगदीश बालकृष्ण तरे एवं विभाग प्रमुख महेश सुरेश पावशे उपस्थित रहे।

संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य अभियंता के समक्ष फ्लोर मिल संचालकों की विभिन्न समस्याएं रखीं। इनमें समय पर बिजली बिल न मिलना, चक्की के अंदर लगे मीटर को बाहर स्थानांतरित करने की मांग तथा बिजली बिल में देरी होने पर उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले फाइन चार्ज का मुद्दा प्रमुख रूप से शामिल रहा।

इसके अलावा जनवरी माह में जिन चक्कियों के मीटर बदले गए थे, उन नए मीटरों को अब तक जनरेट नहीं किए जाने की समस्या भी उठाई गई। पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को पुराने मीटर के आधार पर ही बिजली बिल प्राप्त हो रहे हैं।

एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रधारी यादव ने मुख्य अभियंता को बताया कि संगठन की ओर से कई बार पत्र और निवेदन दिए गए, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। इस पर मुख्य अभियंता चंद्रमणि मिश्रा ने संगठन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुख्य अभियंता के आश्वासन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने उनका आभार व्यक्त किया।

हरित क्रांति का संकल्प: संकट मोचन से उठी पर्यावरण बचाने की हुंकार

◆विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर महंत प्रो. विश्वम्भरनाथ मिश्र ने किया वृहद वृक्षारोपण, छात्रों और समाज को दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश

सुरेश गांधी

वाराणसी। बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट के बीच काशी से हरित क्रांति की एक मजबूत पहल सामने आई। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर संकट मोचन फाउंडेशन और मदर्स फॉर मदर के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को शहर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान का शुभारंभ संकट मोचन मंदिर के महंत एवं संकट मोचन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. विश्वम्भरनाथ मिश्र ने पौधरोपण कर किया। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना आज केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता बन चुका है। अभियान के तहत नगवा स्थित तुलसी विद्या निकेतन (टीवीएन) परिसर और संकट मोचन मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। महंत प्रो. विश्वम्भरनाथ मिश्र ने कहा कि जिस गति से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उससे भविष्य की पीढ़ियों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में वृक्षारोपण ही प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे केवल पौधे लगाएं ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं।

कार्यक्रम में पूर्व आईआईटी-बीएचयू निदेशक प्रो. एस.एन. उपाध्याय, बीएचयू के प्रो. एन.के. दुबे, अदिति मिश्रा, सुमेधा मिश्रा, तुलसी विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य एस.एन. श्रीवास्तव सहित अनेक शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। विद्यालय के छात्रों ने भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेशों के माध्यम से जागरूकता का संकल्प दोहराया। आयोजकों ने कहा कि आज लगाए गए पौधे आने वाले वर्षों में स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन का आधार बनेंगे। अभियान के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। काशी से शुरू हुई यह हरित पहल आने वाले दिनों में व्यापक जनभागीदारी का आधार बनेगी।

अहमदाबाद में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से बड़ा संकट, नर्मदा लाइन में मिला सीवर का पानी, सैकड़ों बीमार

अहमदाबाद, 04 जून। अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां बीते चार दिनों के दौरान सैकड़ों लोग अचानक बीमार पड़ गए हैं। प्रभावित लोगों में दस्त, उल्टी और पेट संबंधी समस्याओं के लक्षण देखे गए हैं। स्थानीय लोगों और नगर प्रशासन के अनुसार इस स्वास्थ्य संकट की वजह पेयजल आपूर्ति में दूषित पानी का मिलना माना जा रहा है।

बता दें कि घाटलोडिया क्षेत्र की कई आवासीय सोसायटियों के निवासियों ने शुक्रवार से ही पानी में बदबू और गंदगी की शिकायतें शुरू कर दी थीं। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुरूआती शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए और बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे हैं।

4 साल में पंजाब ने शिक्षा में 27वें से पहले स्थान पर आकर रचा इतिहास: अरविंद केजरीवाल

पंजाब, 04 जून। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शिक्षा क्षेत्र में पंजाब के प्रदर्शन की सराहना करते हुए दावा किया कि नीति आयोग के सर्वेक्षण में राज्य ने केरल को पीछे छोड़ते हुए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि पंजाब, जो पहले एक मूल्यांकन में 27वें स्थान पर था, अब 2022 में आप सरकार के सत्ता में आने के चार साल के भीतर ही शिक्षा के क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच गया है।

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब, जो कभी सरकारी स्कूलों की शिक्षा में 27वें स्थान पर था, अब पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसने केरल जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारी सरकार 2022 में बनी थी। और 2020 के सर्वेक्षण में पंजाब 27वें स्थान पर था। 27वें स्थान से पहले स्थान तक पहुंचने में हमारी सरकार को केवल चार साल लगे हैं। सरकारी स्कूलों में इसे ऐतिहासिक परिवर्तन बताते हुए, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि यह उपलब्धि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुधारों पर पार्टी के फोकस को दशार्ती है।

उन्होंने कहा कि आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। पंजाब ने पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह हमारा सर्वेक्षण नहीं है; यह केंद्र सरकार के नीति आयोग का शिक्षा सर्वेक्षण है। महज चार वर्षों में 27वें स्थान से पहले स्थान पर आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बहुत उम्मीद जगती है। अगर हम चाहें तो यह कर सकते हैं। यह इरादे की बात है।

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 पर विशेष

पर्यावरणीय संकट से समाधान की ओर बढ़ने का समय

-ललित गर्ग

5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य को बचाने का वैश्विक संकल्प है। वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम ह्लप्लास्टिक प्रदूषण का अंतह्व (ठमंज च्संेजपब च्वससनजपवद) केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति-विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण- ये तीनों संकट परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आज भी दुनिया उस दिशा में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विश्व के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े संकट को भारत की राजनीति में वह महत्व नहीं मिला, जिसका वह अधिकारी है। चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरण का उल्लेख तो होता है, लेकिन वह केवल औपचारिकता भर रह जाता है। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वोट दिलाने वाले मुद्दे नहीं हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रश्न न तो चुनावी बहस का हिस्सा बनते हैं और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का। जबकि सच्चाई यह है कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी प्रश्न पर निर्भर करती है।

पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति को पूजनीय माना है। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखा गया। आयुर्वेद और वनौषधि विज्ञान इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों ने हजारों वर्षों तक मानव स्वास्थ्य की रक्षा की, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह ज्ञान और प्राकृतिक संपदा दोनों उपेक्षित होते गए। आज जब नई-नई बीमारियां मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, तब पुनः प्रकृति और वनस्पति जगत की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि ह्यगरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है। आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि गरीबी और पर्यावरणीय विनाश एक-दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन गए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों की कमी नहीं है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से लेकर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए। लेकिन कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई बनी हुई है। अवैध खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनदेखी और पर्यावरणीय मंजूरियों में शिथिलता इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थागत इच्छाशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है।

फिर भी आशा की किरण दिखाई देती है। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में युवाओं ने जलवायु संकट को गंभीर विषय माना है और सरकार से इस संबंध में शिक्षा एवं जनजागरण की अपेक्षा की है। यह संकेत है कि नई पीढ़ी पर्यावरण को केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि अपने भविष्य का प्रश्न मान रही है। आवश्यकता इस चेतना को सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में बदलने की है। समाधान क्या है? सबसे पहले विकास और पर्यावरण को विरोधी नहीं, पूरक मानने की दृष्टि विकसित करनी होगी। ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना, जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान बनाना, वृक्षारोपण को जनांदोलन का रूप देना और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। केवल सरकारी योजनाओं से यह कार्य संभव नहीं होगा, इसके लिए समाज, उद्योग, शिक्षा संस्थानों और नागरिकों की साझी भागीदारी चाहिए।

दूसरा, पर्यावरण को राजनीतिक एजेंडा बनाना होगा। जिस प्रकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य चुनावी मुद्दे बनते हैं, उसी प्रकार स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हरित विकास और जलवायु सुरक्षा भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनें। मतदाता अपने प्रतिनिधियों से पर्यावरण संबंधी दृष्टि और प्रतिबद्धता के बारे में प्रश्न पूछें। जब जनता पर्यावरण को प्राथमिकता देगी, तब राजनीति भी उसकी ओर मुड़ेगी। तीसरा, शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरणीय चेतना को व्यवहारिक रूप से शामिल करना होगा। बच्चों और युवाओं को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के व्यावहारिक संस्कार दिए जाने चाहिए। चौथा, हमें अपनी जीवनशैली में परिवर्तन लाना होगा। अत्यधिक उपभोग, अपव्यय और सुविधावादी संस्कृति ने पर्यावरणीय संकट को बढ़ाया है। संयमित उपभोग, पुनर्चक्रण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और प्रकृति के प्रति संवेदनशील जीवनशैली ही स्थायी समाधान दे सकती है। यह दृष्टि भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों में पहले से विद्यमान है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हमें यह स्मरण कराता है कि पर्यावरण का प्रश्न केवल पेड़-पौधों या नदियों का प्रश्न नहीं है यह मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न है। यदि हमने समय रहते अपनी नीतियों, विकास मॉडल और जीवनशैली में परिवर्तन नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। लेकिन यदि हम सजगता, वैज्ञानिक दृष्टि, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक सहभागिता के साथ आगे बढ़ें, तो संकट को अवसर में बदला जा सकता है। भारत के पास विश्व को नई दिशा देने की क्षमता है। प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व, अहिंसा, संयम और संतुलित विकास की भारतीय दृष्टि आज पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। आवश्यकता केवल इतनी है कि पर्यावरण को विकास का विकल्प नहीं, विकास का आधार माना जाए। यही विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश है, यही भविष्य की सुरक्षा का मार्ग है और यही पृथ्वी के प्रति हमारी सच्ची जिम्मेदारी है।

आज 5 जून को मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस- एक पेड़ लगाकर दिवस को सफल बनाना जरुरी बनाएं

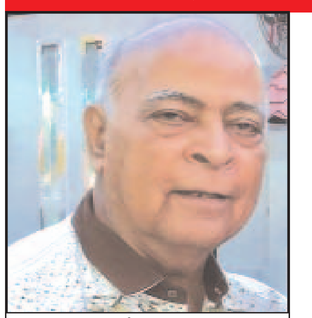

अशोक भाटिया

विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए सबसे प्रसिद्ध दिन है। यह सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। 1974 से यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है। हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, और जो जलवायु हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाती है, वह सब प्रकृति से आती है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख माध्यम है। यह सतत विकास लक्ष्यों के पर्यावरणीय आयामों पर प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इसके अलावा, यह 100 से अधिक देशों में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, पृथ्वी और पर्यावरण के लिए उनकी देखभाल और समर्थन दिखाने के लिए इसे लोकप्रिय रूप से पीपुल्स डे कहा जाता है। पर्यावरण की रक्षा के तरीकों को जानना महत्वपूर्ण है ।

मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिह्नित करने के लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में केवल एक पृथ्वी विषय के साथ आयोजित किया गया था। 1987 से, विश्व पर्यावरण दिवस के लिए विभिन्न गतिविधियों के केंद्र को घुमाने के विचार के साथ विभिन्न मेजबान देशों का चयन किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरूआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। आज यह दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणीय अभियानों में से एक बन चुका है, जिसमें 150 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं। हर साल एक नई थीम और मेजबान देश के साथ यह दिवस मनाया जाता है, ताकि किसी विशेष पर्यावरणीय समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जा सके।

साल 2026 में भी विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ मनाया जा रहा है। इस बार का फोकस प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या पर है, जो समुद्रों, नदियों, वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य तक को प्रभावित कर रही है। आइए जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसकी 2026 की थीम क्या है और इसका इतिहास क्या कहता है।

धरती बहस नहीं करती, समझौता नहीं करती। वह संकेत भेजती है– बढ़ता समुद्र स्तर, भयंकर जंगल की आग, लू, पिघलते ग्लेशियर। हमने कहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा है। हम इसे पार कर रहे हैं। दशकों से दुनिया जलवायु परिवर्तन की कहानी सुनती आ रही है–चेतावनी, लक्ष्य, दूर की समय सीमाएँ। लेकिन अक्सर, प्रतिक्रिया शोरगुल से घिरी रही है: देरी, ध्यान भटकाना, इनकार करना। लेकिन अब ध्यान से सुनिए। शोरगुल के बीच एक और संकेत उभर रहा है। छतों पर सौर पैनल लगे हैं। क्षितिज पर पवन टरबाइन दिखाई दे रहे हैं। शहरों को लोगों के लिए नया रूप दिया जा रहा है। जंगलों को फिर से लगाया जा रहा है। धरती के हर कोने में सकारात्मक बदलाव के संकेत पनप रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है–पृथ्वी द्वारा भेजे जा रहे गंभीर संकेतों और हमारे द्वारा बदले में भेजे जाने वाले संकेतों पर। यूएनईपी का वैश्विक अभियान हम सभी से आगे बढ़कर, इस परिवर्तन की दिशा में और अधिक प्रयास करने का आह्वान करता है। प्रश्न अब यह नहीं है कि परिवर्तन आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि हम इसे कैसे निर्देशित करते हैं और यह कितनी तेजी से होता है। इस वर्ष 5 जून 2026 को, अजरबैजान गणराज्य बाकू में विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी कर रहा है। ऐतिहासिक सिल्क रोड पर पूर्व और पश्चिम के चौराहे पर स्थित, अजरबैजान उल्लेखनीय प्राकृतिक विविधता की भूमि है। इसका भूभाग दो प्रमुख जलवायु क्षेत्रों - उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण - में फैला हुआ है और इसमें उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र तक 8 अलग-अलग प्रकार की जलवायु शामिल हैं, जो समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती हैं। अजरबैजान हरित विकास और नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा दे रहा है । पेरिस समझौते के सदस्य के रूप में, इसने 2035 तक उत्सर्जन को 40% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है (1990 के स्तर से)। इसका लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 30% तक बढ़ाना भी है । 230 मेगावाट का गरादाघ सौर संयंत्र और 240 मेगावाट का खिजी-अबशेरोन पवन ऊर्जा संयंत्र सहित कई बड़े पैमाने की परियोजनाएं चल रही हैं, साथ ही 1 गीगावाट से अधिक क्षमता वाली अतिरिक्त परियोजनाएं विकास के चरण में हैं।

बाकू में आधुनिक कम और शून्य उत्सर्जन वाली बसों , इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी समाधानों के साथ शहरी स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है। गरबाग और पूर्वी जंगेजूर क्षेत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और संघर्ष के बाद के विकास को मिलाकर ?शून्य उत्सर्जन क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। आधुनिक जल प्रबंधन और जलवायु-अनुकूल कृषि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनुकूलन को और मजबूत कर रहे हैं। अजरबैजान ने 2019 से पर्यावरण पर प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के नकारात्मक प्रभाव को कम करने पर केंद्रित अपनी पर्यावरण नीति को आगे बढ़ाया है और इसके लिए कार्य योजना को अपनाया है। नए विधायी सुधारों के माध्यम से इसने 15 माइक्रोन तक की मोटाई वाले एकल-उपयोग प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग के आयात, उत्पादन, साथ ही व्यापार, सार्वजनिक खानपान और अन्य सेवा सुविधाओं में उपभोक्ताओं को बिक्री या आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मेजबान के रूप में, अजरबैजान ने वैश्विक जलवायु एजेंडा को आगे बढ़ाया, जलवायु वित्त और कार्बन बाजारों पर ऐतिहासिक निर्णय हासिल किए, साथ ही जलवायु कार्रवाई को जैव विविधता, ऊर्जा संक्रमण, जल, कृषि और सामाजिक प्रभाव से जोड़ने वाली पहल शुरू की। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, अजरबैजान का विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के लिए राष्ट्रीय अभियान जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के वैश्विक संकटों और लोगों तथा प्रकृति पर उनके परस्पर जुड़े प्रभावों पर प्रकाश डालता है। प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए? विषय के अंतर्गत, ये पहलें इस बात पर बल देती हैं कि प्रकृति वैकल्पिक नहीं है–यह जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और हमारे सामूहिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, अजरबैजान इस वर्ष आयोजित होने वाले कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण और जलवायु एजेंडा में अपना योगदान और भी बढ़ाएगा। इनमें संयुक्त राष्ट्र-आवास के साथ साझेदारी में मई में आयोजित होने वाला विश्व शहरी मंच का 13 वां सत्र ; जुलाई में शमाखी में संयुक्त राष्ट्र वित्तीय परिषद प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की तीसरी अनौपचारिक बैठक; और संयुक्त राष्ट्र वित्तीय परिषद का बाकू जलवायु कार्रवाई सप्ताह शामिल हैं। गौरतलब है कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हम 5 जून को चंद्र ग्रहण भी देखेंगे। चंद्र ग्रहण, विश्व पर्यावरण दिवस, और शुक्रवार, सभी 5 जून को एक साथ पड़ रहे हैं, इसे ज्योतिषीय रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण अपने साथ किसी न किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। आपकी जन्म कुंडली में कौन सा घर सक्रिय है, इसके आधार पर चंद्र ग्रहण का अलग-अलग चंद्र राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन, आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर एक पेड़ लगाकर ग्रहण के दुष्प्रभावों को नकार सकते हैं। साथ ही, यह ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने और स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है।

अथर्ववेद में पृथ्वी को माता माना गया है और मनुष्य उसके पुत्रों का प्रतीक है। इतना ही नहीं वेदों में पेड़-पौधों का महत्व भी बताया गया है। पेड़ हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं और पृथ्वी और आकाश के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक व्यक्ति को पेड़ लगाने से बीमारियों, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। शायद यही एक कारण है कि हमारे पूर्वज वृक्षों की पूजा करते हैं।

टीबीएच, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ लगाकर न केवल हमारी धरती मां का पोषण करेगा बल्कि आपको ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से भी बचाएगा। इसके अलावा, यह आपको ग्रहों के दोषों से छुटकारा पाने में मदद करता है और चंद्र ग्रहण पर दूसरों को पौधे के बीज लगाकर या यहां तक कि जीवन के कई पहलुओं में सुधार कर सकता है। अपनी राशि के अनुसार भाग्यशाली पौधों और पेड़ों के बारे में जानने के लिए हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषियों से सलाह लें!

आइए एक साथ मिलें और इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाएं। यह हमारी जीवन शैली को नियंत्रित करने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, अधिक पेड़ उगाने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके पर्यावरण को बचाने में योगदान करने का समय है। समारोहों का हिस्सा बनें और दुनिया को स्वच्छ, हरा-भरा और उज्जवल बनाएं।

डिजिटल बगावत की दस्तक, क्या सियासत की कसौटी पर टिकेगी?

-अजय कुमार

दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अमूमन गंभीर राजनीतिक बहसों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रवायती नेताओं की सफेद पोशाकों का गवाह बनता रहा है। लेकिन बीते बुधवार को वहां जो कुछ हुआ, उसने भारतीय राजनीति के एक नए और अतरंगे अध्याय की आहट दे दी। तीन पढ़े-लिखे नौजवान मंच पर बैठते हैं और देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बुलंद करते हैं। यह मांग किसी स्थापित विपक्षी दल की तरफ से नहीं, बल्कि एक ऐसे संगठन की ओर से आती है जिसका नाम 'कॉकरोच जनता पार्टी' है। जो कल तक सोशल मीडिया के टाइमलाइन पर महज एक व्यंग्य, डिजिटल मजाक और कड़वे मीम्स का जरिया था, वह अब देश की राजधानी की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। नीट-यूजी और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने देश के युवाओं के भीतर जिस कदर हताशा और आक्रोश भरा है, यह आंदोलन उसी की एक उपज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ डिजिटल स्पेस में वायरल होकर या तंज कसकर देश की जमीनी सियासत को बदला जा सकता है? क्या यह भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की वास्तविक छटपटाहट है या फिर सोशल मीडिया की चमक-दमक के बीच उपजा एक और अल्पकालिक तमाशा?

इस आंदोलन की रीढ़ कहे जाने वाले तीन चेहरे सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका अपने आप में दिलचस्प पृष्ठभूमि रखते हैं। इनमें कोई स्थापित और मझा हुआ राजनेता नहीं है। एक सजग पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आरटीआई के जरिए सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर करते रहे हैं, तो दूसरा ध्रुव राठी जैसे बड़े मंचों के लिए गहरे शोध और स्क्रिप्ट लेखन से जुड़ा रहा है। तीसरे चेहरे को देखें तो वे आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी वैश्विक संस्थाओं से पढ़कर लौटे पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं। ये वो युवा हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, इंटरनेट की बारीकियों को समझते हैं और जिनके पास अपनी बात को आधुनिक तरीके से रखने का सलीका है। आगामी 6 जून को जब इस पार्टी के संस्थापक अमेरिका से दिल्ली लौटेंगे और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाएगी, तब इस डिजिटल गुस्से की पहली असली परीक्षा जमीन पर होगी। पेपर लीक का मुद्दा निश्चित रूप से देश के करोड़ों छात्रों और उनके अभिभावकों के भविष्य से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय है। इस मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी शत-प्रतिशत जायज है, लेकिन इस नाराजगी को अभिव्यक्त करने के लिए 'कॉकरोच' जैसे प्रतीक और विशुद्ध व्यंग्य का सहारा लेना इस आंदोलन की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर देता है। इतिहास गवाह है कि महज आक्रोश और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से कभी भी स्थायी तब्दीली नहीं आती। डिजिटल दुनिया में किसी पोस्ट का ट्रेंड कर जाना या लाखों लाइक्स मिल जाना क्रांति का पैमाना नहीं हो सकता। कॉकरोच पार्टी ने युवाओं के भीतर पनप रहे असली दर्द और बेरोजगारी की कड़वी सच्चाई को बेबाकी से सामने तो रखा है, लेकिन जब बात ठोस और व्यावहारिक एजेंडे की आती है, तो यह संगठन बगलें झांकता नजर आता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश को सिर्फ चुटकुलों, मीम्स और परफॉर्मेंस के सहारे नहीं चलाया जा सकता। एक वक्त के बाद जनता और वक्त दोनों ही मुश्किल सवाल पूछते हैं। नौकरियां कैसे पैदा होंगी? देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सुधारने की क्या योजना है? टैक्स ढांचा, पुलिस सुधार या विदेश नीति पर संगठन की क्या सोच है? इन बुनियादी और जटिल नीतिगत सवालों पर कॉकरोच पार्टी के पास फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं है। राजनीति में इस तरह की अस्पष्टता का एक फायदा जरूर होता है कि विचारधारा के स्तर पर मतभेद नहीं होते और हर तरह का असंतुष्ट तबका आपके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही आप किसी एक गंभीर मुद्दे पर ठोस स्टैंड लेते हैं, आंतरिक अंतर्विरोध और मतभेद सतह पर आने लगते हैं।

इस पूरे नैरेटिव का एक खतरनाक पहलू यह भी है कि यह आंदोलन युवाओं को लगातार नकारात्मकता और व्यवस्था के प्रति घोर निराशा की ओर धकेल सकता है। सत्ता की आलोचना करना और उससे तीखे सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र को ऐसे नागरिकों की भी जरूरत होती है जो यह विश्वास रखें कि मौजूदा तंत्र में सुधार मुमकिन है। जब अदालतें, मीडिया, चुनाव और विश्वविद्यालय जैसी हर संवैधानिक और सामाजिक संस्था सिर्फ उपहास और मजाक का विषय बनकर रह जाएगी, तो आम जनता उन्हें सुधारने की उम्मीद और कोशिश ही छोड़ देगी। यह किसी व्यवस्था के खिलाफ बगावत नहीं, बल्कि उसके सामने आत्मसमर्पण या हार मान लेने जैसी स्थिति है। इसके अलावा, आंदोलन का यह दावा भी पूरी तरह सच नहीं लगता कि यह संघर्ष कर रहे देश के हर आम युवा की आवाज है। जरा इसके अगुआ चेहरों और इसके प्रसार के दायरे को देखिए। यह मुख्य रूप से अंग्रेजी बोलने वाले, बड़े शहरों में रहने वाले और चौबीसों घंटे ऑनलाइन रहने वाले युवाओं का एक खास क्लब नजर आता है। भारत के सुदूर गांवों में रहने वाले युवा, खेतों में पसीना बहाने वाले किसान पुत्र, प्रवासी मजदूर और वे करोड़ों नौजवान जिनके पास स्मार्टफोन या हाई-स्पीड इंटरनेट तक नहीं है, वे इस पूरी तस्वीर से पूरी तरह गायब हैं। इंटरनेट पर लोकप्रियता बटोरना और देश की धूल भरी सड़कों पर उतरकर जनसमर्थन हासिल करना, दोनों दो बिल्कुल अलग छोर हैं।

दूसरी बड़ी व्यावहारिक समस्या यह है कि यह पूरा आंदोलन लगभग एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ शो दिखाई देता है। जब कोई आंदोलन या संगठन किसी एक चेहरे के करिश्मे पर टिक जाता है, तो उस व्यक्ति के पैर डगमगाते ही पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हमारे सामने है, जो एक बड़े जनआंदोलन से उपजे थे, लेकिन बाद में सत्ता के रवायती ढर्रे में ही समा गए। किसी भी वास्तविक राजनीतिक संगठन को चलाने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, प्रशिक्षित कैडर और एक स्पष्ट विचारधारा की आवश्यकता होती है। सोशल मीडिया का मौजूदा मॉडल ही इस तरह तैयार किया गया है जो केवल नाराजगी, उत्तेजना और सनसनी को बढ़ावा देता है। अगर किसी आंदोलन के पास साफ सिद्धांत और अनुशासन की सीमाएं न हों, तो ऐसे मंच बहुत जल्दी अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों के आसान निशाने बन जाते हैं। एक असहज करने वाली सच्चाई यह भी है कि मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठानों को अक्सर इस तरह का मीम-आधारित विपक्ष रास आता है। वायरल पोस्ट और मजेदार तंज वाली यह डिजिटल बगावत उस वास्तविक युवा ऊर्जा को बिखेर देती है, जो अन्यथा एक गंभीर चुनावी या राजनीतिक चुनौती में बदल सकती थी। किसी भी मजबूत सरकार के लिए सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाना उतना बड़ा खतरा नहीं होता, जितना बड़ा डर एक संगठित, अनुशासित और जमीनी स्तर पर काम करने वाले विपक्ष से होता है। यहाँ तक कि पार्टी का चुनाव-चिह्न 'कॉकरोच' भी एक दोधारी तलवार की तरह है। भले ही यह जीव हर विपरीत परिस्थिति में जिंदा रहने की क्षमता रखता हो, लेकिन आम जनमानस में उसकी पहचान गंदगी, संक्रमण और घृणा से ही जुड़ी होती है। जब कोई प्रतीक जनता के बीच जाता है, तो वह अपने मूल अर्थ से इतर एक अलग ही छवि बना लेता है।

लब्बोलुआब यह है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और वास्तविक राजनीतिक ताकत दो अलग-अलग चीजें हैं। वर्चुअल दुनिया किसी भी आंदोलन को कृत्रिम रूप से बहुत विशाल और प्रभावी दिखा सकती है, लेकिन यह ऑनलाइन लोकप्रियता उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है, जितनी तेजी से स्क्रीन पर स्क्रॉल होती है। जैसे ही कोई नया वायरल मुद्दा आता है, लोग पुरानी बहसों को भूल जाते हैं। वास्तविक और स्थायी बदलाव के लिए धैर्य, वर्षों की कड़ी मेहनत और संगठन खड़ा करने का वह उबाऊ काम करना पड़ता है, जो इंटरनेट के इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल है। भारत का युवा बेरोजगारी, महंगाई और एक संवेदनहीन व्यवस्था से सचमुच परेशान है और उसका गुस्सा शत-प्रतिशत वास्तविक है। इस गुस्से को चर्चा के केंद्र में लाने का श्रेय इस डिजिटल मुहिम को दिया जा सकता है, लेकिन किसी समस्या को रेखांकित करना और उसका व्यावहारिक समाधान निकालना, दो अलग बातें हैं। जब तक यह मजाक, तंज और मीम्स एक ठोस नीतिगत योजना में नहीं बदलते, तब तक यह कवायद भी इतिहास की उन कई इंटरनेट सनसनियों की तरह ही दर्ज होगी, जो देखने में तो बड़ी क्रांति जैसी लगीं, लेकिन अंततः व्यवस्था में कोई वास्तविक बदलाव नहीं ला सकीं।

वैश्विक शोर, बहुपक्षीय चुनौतियाँ और अदृश्य खतरे में मानवता का भविष्य

सभ्यताओं का अवसान प्रायः किसी आकस्मिक युद्ध, महाविनाशकारी महामारी या त्वरित प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं होता। इसके विपरीत, उनका क्षरण अत्यंत मंद गति से, अदृश्य रूप से, उन आंतरिक सामाजिक विखंडनों और वैचारिक मतभेदों की दरारों से प्रारंभ होता है जिन्हें समाज समय रहते संबोधित करने में विफल रहता है। इतिहास गवाह है कि सबसे गंभीर मानवीय संकट अक्सर वहीं आकार लेते हैं, जहाँ वैश्विक समुदाय की दृष्टि सबसे कम जाती है।

वर्तमान में हम एक ऐसे अभूतपूर्व युग के साक्षी हैं जहाँ सूचना का प्रवाह प्रकाश की गति से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। प्रत्येक क्षण कोई नया संकट, नया भूराजनीतिक विवाद या तात्कालिक सनसनी हमारे डिजिटल पटल पर उभरती है। परिणामस्वरूप, हमारी सामूहिक चेतना अब तथ्यों, गहन शोध और दीर्घकालिक दूरदर्शिता से संचालित होने के बजाय तात्कालिक उत्तेजनाओं के वशीभूत होती जा रही है। इसका दुष्परिणाम यह है कि हम उन सतही और क्षणिक घटनाओं पर बहुमूल्य संसाधन और समय व्यर्थ करते हैं जो कुछ समय बाद विस्मृति के गर्त में चली जाती हैं, जबकि उन अंतर्निहित प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर देते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को निर्धारित कर रही हैं।

सूचना का आधिक्य और वैचारिक शून्यता

आधुनिक मानव समाज की सबसे बड़ी विडंबना सूचना का अभाव नहीं, बल्कि 'सूचना का आधिक्य' (Information Overload) है। इस अनियंत्रित प्रवाह के कारण समाज 'महत्वपूर्ण' और 'तत्काल' के बीच का मौलिक अंतर भूल चुका है। जो विषय दृश्य माध्यमों (Screens) पर सर्वाधिक प्रसारित होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगता है, भले ही धरातलीय वास्तविकता इसके पूर्णतः विपरीत हो।

यदि वैश्विक समाज केवल पारंपरिक बाह्य सुरक्षा और सीमाओं के खतरों से आशंकित है, किंतु अपने भीतर पनपती वैचारिक असहिष्णुता, बहुपक्षीय और लोकतांत्रिक संस्थाओं में घटते जनविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य के मूक संकट, तीव्र पर्यावरणीय क्षरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अनियंत्रित सामाजिकराजनीतिक प्रभावों को गौण मान रहा है, तो वह वस्तुतः एक व्यापक वैश्विक संकट को आमंत्रित कर रहा है। किसी भी राष्ट्र या समाज की वास्तविक संप्रभुता और शक्ति उसके सैन्य शस्त्रागार या आर्थिक प्रभुत्व में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की सत्य को पहचानने और विवेकपूर्ण निर्णयन की क्षमता में निहित होती है। जब समाज तथ्य और कल्पना, वैज्ञानिक शोध और भ्रामक अफवाहों, तथा तर्क और सुनियोजित दुष्प्रचार (Propaganda) के बीच की विभाजन रेखा को खो देता है, तब उसका बौद्धिक आधार ढहने लगता है। ऐसी स्थिति में असत्य केवल एक नैतिक शिथिलता नहीं रह जाता, बल्कि वह एक सामाजिक, राजनीतिक और सभ्यतागत संकट का रूप ले लेता है।

अटेंशन इकॉनमीः ध्यान भटकाने का वैश्विक तंत्र

सोशल मीडिया के एल्गोरिदम पर आधारित वर्तमान सूचना तंत्र ने इस चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। इन डिजिटल मंचों का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक नागरिकों को अधिक विवेकशील, जागरूक या संवेदनशील बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्क्रीन पर निरंतर व्यस्त रखना है। यही कारण है कि जो सामग्री भय, आक्रोश, घृणा या सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, वह सबसे तीव्र गति से प्रसारित होती है। शनैःशनैः, वैश्विक विमर्श तथ्य, तर्क और मानवीय मूल्यों की ठोस भूमि से विस्थापित होकर भावनात्मक आवेगों के प्रवाह में बहने लगता है।

यह केवल सूचना का संकट नहीं है; यह 'अटेंशन इकॉनमी' (Attention Economy) के दौर में मानवीय एकाग्रता का संकट है। आज के युग में मानवता की सबसे बहुमूल्य पूँजी वित्तीय संसाधन नहीं, बल्कि उसकी एकाग्रता और सोचने की क्षमता है। जिस समाज का ध्यान निरंतर भटकाया जा सकता है, उसकी दिशा और दशा को भी वैश्विक स्तर पर सुगमता से नियंत्रित किया जा सकता है।

पर्यावरण और तकनीकः अस्तित्व के दो निर्णायक मोड़

पर्यावरणीय संकट इस प्रवृत्ति का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी एक दिन का भीषण चक्रवात या बाढ़ तात्कालिक रूप से वैश्विक सुर्खियाँ तो बन जाते हैं, लेकिन दशकों से धीरेधीरे परिवर्तित होता वैश्विक जलवायु चक्र केवल एक सामान्य सांख्यिकीय समाचार बनकर रह जाता है। डिजिटल मंचों पर कोई सतही विषय करोड़ों लोगों तक क्षण भर में पहुँच जाता है, परंतु भूजल के लगातार गिरते स्तर, मिट्टी की घटती उर्वरता और जैव विविधता के अपरिवर्तनीय विनाश (Biodiversity Loss) पर कोई ठोस और निर्णायक वैश्विक आम सहमति या विमर्श स्थापित नहीं हो पाता।

यही स्थिति कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के उदय की भी है। एआई का विकास केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना और सभ्यता के विकासक्रम में एक अभूतपूर्व मोड़ है। इस मोड़ पर वास्तविक चिंता यह नहीं है कि मशीनें मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो जाएँगी; बल्कि गहरी चिंता यह है कि कहीं इस तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता के चलते मनुष्य स्वयं मौलिक चिंतन करना, असहज करने वाले प्रश्न पूछना, स्वस्थ संदेह व्यक्त करना और स्वतंत्र रूप से सोचना ही न छोड़ दे। यदि हमारे जीवन के नीतिगत निर्णय एल्गोरिदम द्वारा संचालित होंगे, डिजिटल मंच हमारी मानवीय संवेदनाओं को नियंत्रित करेंगे और सत्य का पैमाना केवल 'वायरल होना' रह जाएगा, तो भविष्य का सबसे बड़ा संकट तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय विवेक के अवसान का होगा।

अपरिहार्य की पहचान और बौद्धिक उत्तरदायित्व

इतिहास साक्ष्य है कि महान सभ्यताएँ केवल तब तक जीवित और जीवंत रहती हैं, जब तक वे असुविधाजनक किंतु आवश्यक प्रश्न पूछने का साहस रखती हैं। जो समाज दीर्घकालिक परिवर्तनों की उपेक्षा करके केवल तात्कालिक घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया (Reactive Mode) देता है, वह अंततः अपनी ही बुनी हुई आभासी धारणाओं के जाल में कैद होकर रह जाता है। शायद हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हमें दृश्य खतरों से कितना डरना चाहिए, बल्कि यह है कि हम क्रमिक रूप से बढ़ते उन अदृश्य विनाशों को अनदेखा करने के इतने अभ्यस्त क्यों हो चुके हैं कि उन्हें संकट मानना ही छोड़ बैठे हैं।

यह पूर्णतः संभव है कि आने वाले दशकों में मानवता यह स्वीकार करे कि उसके सामने सबसे बड़ा संकट कोई पारंपरिक युद्ध, महामारी या आर्थिक मंदी नहीं थी; बल्कि सबसे बड़ा संकट यह था कि उसने बाहरी कोलाहल को ही अंतिम सत्य मान लिया और मौन की कोख में पनप रही क्रांतियों को सुननेसमझने की क्षमता खो दी। सभ्यताओं का भविष्य उन्हीं के हाथों में सुरक्षित रहता है जो केवल तात्कालिक 'सेंसेशन' को नहीं, बल्कि उन अनिवार्य और अपरिहार्य सत्यों को पहचान लेते हैं जो अत्यंत धीमे, मौन किंतु निश्चित रूप से इतिहास की दिशा बदल रहे होते हैं। सतत विकास (Sustainable Development) और वैश्विक शांति के इस दौर में हमारे समय की सबसे बड़ी बौद्धिक और नैतिक जिम्मेदारी भी यही है, उस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत होना, जिसे बहुसंख्यक समाज देख नहीं पा रहा, या जिसे देखकर भी विश्व वास्तव में चिंतित नहीं है।

- राजकुमार जैन, स्वतंत्र चिंतक

महंगाई के खिलाफ घाटकोपर में शिवसेना ठाकरे गुट का जोरदार प्रदर्शन

रेलवे स्टेशन के बाहर आंदोलन, जनता को मेलोडी चॉकलेट बांटकर केंद्र सरकार का किया विरोध

मुंबई (उत्तरशक्ति)। बढ़ती महंगाई, रसोई गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतों तथा आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ के विरोध में आज शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से घाटकोपर पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर जोरदार आंदोलन किया गया। विभाग प्रमुख सुरेश पाटिल के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शिवसैनिकों, महिला पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने भाग लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इस आंदोलन में महिला विभाग प्रमुख प्रज्ञा सकपाल, नगरसेविका स्वरूपा पाटिल, नगरसेविका सकीना शेख, विधानसभा प्रमुख सुभाष पवार, शाखा प्रमुख अजय भोसले सहित अनेक पदाधिकारी और शिवसैनिक उपस्थित थे।

आंदोलन के दौरान महंगाई कम करो, आम जनता को राहत दो तथा गैस सिलेंडर की कीमतें वापस लो जैसे नारों के माध्यम से सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की ओर से कड़ा बंदोबस्त किया गया था। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन कार्यकताओं में सरकार के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दी।

इस अवसर पर विभाग प्रमुख सुरेश पाटिल ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों के कारण देश की आम जनता परेशान है। महंगाई लगातार

बढ़ रही है और आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों ने गृहिणियों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है।

परिवार का खर्च चलाना महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार को महंगाई पर नियंत्रण के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए।

आंदोलन की विशेषता यह रही कि शिवसैनिकों ने उपस्थित नागरिकों के बीच मेलोडी चॉकलेट का वितरण किया। इस अनोखे तरीके से महंगाई के मुद्दे पर सरकार का विरोध जताया गया। शिवसेना (ठाकरे गुट) के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

पर्यावरण संरक्षण और मानवीय सेवा की दिशा में मेघाश्रेय की अनोखी पहल

मुंबई (उत्तरशक्ति)। एक पेड़ माँ के नाम' भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक भावनात्मक और पर्यावरण-अनुकूल अभियान है। इसके तहत लोग अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्रेम जताने के लिए उनकी स्मृति या उपस्थिति में एक पेड़ लगाते हैं और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेते हैं। मेघाश्रेय संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बांद्रा फोर्ट में एक ऐसे ही अनूठे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, आईपीएस कृष्णा प्रकाश, आईपीएस विश्वास नांगरे पाटील, स्टीफन बेन, नूपुर सनोन, डीनो मोरिया,आसिफ भामला,कविन शाह,गौरव पारिख, मिकी मेहता जैसी अनेक जानी-मानी हस्तियों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस सशक्त आंदोलन को और भी मजबूत बनाया और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हाथ बंटाया। मेघाश्रेय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विगत वर्षों की तरह छाता, रेनकोट और पानी का वितरण किया गया। सीमा सिंह द्वारा आयोजित इस पहल में एक साथ तीन सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों की पूर्ति की गई। जीवन के लिए पानी, आराम के लिए छाया, और भविष्य के लिए पेड़ की संकल्पना वाले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बीएमसी कर्मचारी उपस्थित रहे। सीमा सिंह के अनुसार बढ़ रही पर्यावरण चुनौती के बीच हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकट परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में वृक्ष ही हमारे जीवन दाता बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, इससे मां, मातृभूमि और धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त होगी। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और हर व्यक्ति को इस धर्म का पालन करना चाहिए।

भिवंडी में नाला सफाई को लेकर महापौर का दावा हवा-हवाई, नगरसेवकों ने नाराजगी जताकर दिखाया आक्रोश

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी शहर में नाला सफाई को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मनपा क्षेत्र में बारिश से पहले नालों की सफाई पूरी करने के महापौर नारायण चौधरी के दावे पर सवाल उठाते हुए प्रभाग समिति क्रमांक-5 के सभापति एडवोकेट वैभव भोईर ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका आरोप है कि नाला सफाई का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल 30 से 40 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। एड. वैभव भोईर ने नगरसेवक एड. मयुरेश पाटिल, नेहा काठवले, रोमा आलशी, मलिक मोमिन और फाम अंसारी के साथ प्रभाग के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन प्रशासन और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण नालों की सफाई अधूरी है। उन्होंने बताया कि प्रभाग समिति क्रमांक-5 शहर का अंतिम क्षेत्र है, जहां शहर के अधिकांश नाले खाड़ी में जाकर मिलते हैं। यदि यहां समय पर नालों की सफाई नहीं हुई तो शहर के कई हिस्सों का पानी जमा होकर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इससे नागरिकों के जान-माल को भारी नुकसान होने की आशंका है। एड. भोईर ने आरोप लगाया कि महापौर द्वारा बारिश से पहले नाला सफाई पूरी कराने की घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नागरिकों को जलभराव की समस्या से बचाने के लिए ठेकेदारों को तत्काल कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही चेतावनी दी कि यदि नाला सफाई का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित ठेकेदारों का भुगतान रोका जाए। उन्होंने कहा कि नाला सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए प्रशासन और ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

CoinDCX ने सतर्क रहे साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया

मुंबई। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने आज सतर्क रहे नामक सोशल-फर्स्ट साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान की घोषणा की। यह पहल भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और गृह मंत्रालय के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। इसका शुभारंभ साइबर जागरूकता दिवस के अवसर पर किया गया, जिसे I4C और गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय पहल के तहत हर महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। सतर्क रहे अभियान CoinDCX के डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार है। DSN 100 करोड़ की पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना और पूरे भारत में साइबर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करना है। सतर्क रहे को इस तरह तैयार किया गया है कि यह लोगों को आम डिजिटल धोखाधड़ी पहचानने और उनसे निपटने में मदद करे। यह पहल सतर्क नामक किरदार पर आधारित है और सोशल मीडिया पर रोजमर्रा की स्थितियों और बातचीत के अंदाज का इस्तेमाल करती है। इसका मकसद है कि साइबर सुरक्षा शिक्षा को सरल, संबंधित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ बनाया जाए, ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें और अपने डिजिटल जीवन में लागू कर सकें। श्री निशांत कुमार, निदेशक, भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर , गृह मंत्रालय ने कहा, साइबर अपराधी लगातार नए और जटिल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अनजान लोगों को निशाना बनाया जा सके। वर्षों से I4C ने कई सार्वजनिक जागरूकता पहलें की हैं, जिनमें सोशल मीडिया हैंडल CyberDost और अन्य राष्ट्रीय स्तर के आउटरीच अभियान शामिल हैं।

'मेड इन इंडिया - द टाइटन स्टोरी' से जुड़ा हमदर्द लेबोरेट्रीज

मुंबई। हमदर्द लेबोरेट्रीज इंडिया ने मशहूर अभिनेता जिम सरभ अभिनीत आगामी वेब सीरीज मेड इन इंडिया-द टाइटन स्टोरी के सह-प्रायोजक के रूप में अपनी साझेदारी की घोषणा की है। यह सीरीज भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्वदेशी ब्रांडों में से एक के सफर और उसके स्थायी सांस्कृतिक व उद्यमशीलता के प्रभाव को दर्शाती है। यह एसोसिएशन जिम सरभ के साथ हमदर्द के पिछले सहयोग यूनानी की कहानी को और आगे बढ़ाता है, जो एक डॉक्यूमेंट्री-आधारित पहल थी। इसमें यूनानी चिकित्सा के इतिहास, दर्शन और प्रासंगिकता के साथ-साथ भारत में हमदर्द की सदियों पुरानी विरासत को दिखाया गया था। इस वेब सीरीज का टीजर पहले ही २६ मई २०२६ को रिलीज किया जा चुका है, जबकि पूरी वेब सीरीज आज, ३ जून २०२६ को अमेजॅन एमएक्स प्लेयर पर प्रीमियर के लिए तैयार है। एक सदी से भी अधिक पुराने इतिहास वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांड के रूप में, मेड इन इंडिया-द टाइटन स्टोरी के साथ हमदर्द का यह जुड़ाव उन स्वदेशी संस्थानों को सम्मानित करने की एक साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है, जिन्होंने पीढ़ियों से उपभोक्ताओं का भरोसा जीता है। इस सहयोग के माध्यम से, हमदर्द उन कहानियों को समर्थन देना चाहता है जो भारतीय उद्यमिता, विरासत, नवाचार और सांस्कृतिक रूप से जुड़े उन ब्रांड्स के सफर को उजागर करती हैं, जो आधुनिक भारत में आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस साझेदारी के तहत, हमदर्द को वेब सीरीज के पूरे इकोसिस्टम में एकीकृत दृश्यता मिलेगी। यह पार्टनरशिप टाइमलेस टेल्स विद जिमह्व (खे के साथ कालजयी कहानियाँ) के बैनर तले विशेष सप्लीमेंट्री कंटेंट तक भी विस्तारित होगी।

केवणी और काल्हेर में अवैध बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, बालू के 23 भंडारण कुंडों को किया गया ध्वस्त

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। ठाणे जिला प्रशासन के निर्देश पर भिवंडी तहसील प्रशासन ने गुरुवार को केवणी और काल्हेर क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए 23 अवैध बालू भंडारण कुंडियों को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। जिलाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल, अपर जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल तथा उपविभागीय अधिकारी अमित सानप के मार्गदर्शन में तहसीलदार अभिजीत खोले के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई में मंडल अधिकारी सुधाकर कामडी, शैलेश भोजने, गणेश विशे और

रविंद्र काले के नेतृत्व में राजस्व विभाग, वन विभाग, कांदलवन संरक्षण इकाई, भिवंडी ग्रामीण व नारपोली पुलिस, पंचायत समिति तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि केवणी और काल्हेर स्थित आरक्षित वन तथा गुरूचरण भूमि क्षेत्रों में खाड़ी से अवैध रूप से निकाली गई बालू के भंडारण के लिए बड़ी संख्या में कुंडियां बनाई गई थीं। इनका उपयोग चोरी से लाई गई बालू को जमा करने के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मौजा केवणी के सर्वे नंबर 181/अ क्षेत्र में 15 तथा आरक्षित वन एवं काल्हेर क्षेत्र में 8 अवैध कुंडियों को ध्वस्त किया गया। इस प्रकार कुल 23 अवैध बालू भंडारण कुंडों को पूरी तरह नष्ट कर दी गईं। राजस्व विभाग की जांच में सामने आया कि इन कुंडों में खाड़ी से अवैध रूप से निकाली गया बालू बड़े पैमाने पर जमा की जा रही थी। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से अवैध रेत कारोबार की पूरी श्रृंखला को बड़ा झटका लगा है। उल्लेखनीय है कि भिवंडी तहसील प्रशासन द्वारा अवैध बालू उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार की यह कार्रवाई उसी अभियान का एक महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है, जिससे अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

महंगाई में कमी नहीं आई तो कांग्रेस घर-घर जाकर करेगी आंदोलन : भावना शर्मा जैन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद वर्षा गायकवाड़ के मार्गदर्शन तथा उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भावना शर्मा जैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा जोगेश्वरी पूर्व में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस अवसर पर भावना शर्मा जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से केवल मन की बात करते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बचते हैं। आज पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार राहत में भी फेल हो रही है । उन्होंने कहा कि देश की

शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर संकट से गुजर रही है । नीट और सीबएसई जैसी परीक्षाओं में हुए कथित घोटालों और पेपर लिक की घटनाओं ने देश की युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज 17 वर्ष के युवा भी अपनी आवाज उठाने और व्यवस्था की खामीयों को उजागर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। भावना शर्मा जैन ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल एवं गैस की कीमतों में तत्काल कमी कर जनता को राहत देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द महंगाई में कमी नहीं की गई तो राहुल गांधी और वषार्ताई गायकवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस का यह जन आंदोलन और अधिक व्यापक एवं तीव्र उग्र होगा तथा इसे घर-घर और गली-गली तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के विभिन्न विभागों महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

भिवंडी के बढ़ते प्रदूषण पर भाजपा नगरसेविका स्नेहा पाटिल ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से दोषियों पर एफआईआर की मांग

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर भाजपा नगरसेविका स्नेहा मेहुल पाटिल ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) के अध्यक्ष सिद्धेश कदम से मुंबई में मुलाकात कर शहर की गंभीर पर्यावरणीय स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। स्नेहा पाटिल ने आरोप लगाया कि भिवंडी महानगरपालिका प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्ट कार्यप्रणाली के कारण पूरा शहर प्रदूषण की चपेट में आ गया है। उन्होंने कहा कि शहर के डाइंग-साइजिंग उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा मोती कारखानों में रासायनिक पदार्थों के दहन से वायु गुणवत्ता सूचकांक (अदक) 333 के पार पहुंच गया है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई साइजिंग कारखानों में कोयले के बजाय प्लास्टिक, प्लाईवुड और रासायनिक कचरे को खुलेआम जलाया जा रहा है। इसके

बावजूद प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की मौजूदगी में यह गतिविधियां जारी हैं और संबंधित उद्योग अब भी ग्रीन कैटेगरी में शामिल हैं। उन्होंने ऐसे उद्योगों को तत्काल रेड कैटेगरी में शामिल कर सील करने की मांग की। स्नेहा पाटिल ने यह भी आरोप लगाया कि शहर में प्रतिदिन 75 मीट्रिक टन क्षमता वाला कचरा प्रसंस्करण प्रकल्प केवल कागजों पर ही मौजूद है और वास्तविक रूप से बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि भिवंडी मनपा ने वर्ष 2022 से 2026 तक का एक भी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट (एरफ) सार्वजनिक नहीं किया है। साथ ही वायु गुणवत्ता मापने वाले उपकरण भी बंद रखे गए हैं, जिससे प्रदूषण की वास्तविक स्थिति सामने न आ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मनपा और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्थानीय अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि शहर की जनता शुद्ध हवा के लिए संघर्ष कर रही है। स्नेहा पाटिल ने चेतावनी दी कि यदि आगामी दिनों में प्रदूषण फैलाने वालों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो भिवंडी के नागरिकों को साथ लेकर अधिकारी हटाओ और महापालिका को ताला लगाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

राष्ट्रपति की उपस्थिति में जव्हार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रोजेक्ट को मिला राष्ट्रीय सम्मान

पालघर (उत्तरशक्ति)। आदिवासी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय और परिणामकारक कार्य के लिए जव्हार स्थित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रोजेक्ट (ITDP) को केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला ITDP" का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान के साथ परियोजना को 5 लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ITDA और ITDP के सशक्तिकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। इस अवसर पर जनजाति कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा, अपर सचिव मनीष ठाकुर, तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिरी सहित विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पुरस्कार जव्हार ITDP के प्रोजेक्ट अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर, सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी मच्छिंद्र गडाख और नियोजन अधिकारी सतीश रास्ते ने प्राप्त किया। इस राष्ट्रीय सम्मान के माध्यम से आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए लागू विभिन्न नवीन योजनाओं, प्रभावी कार्यान्वयन, लाभार्थी-केंद्रित पहलों और उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मान्यता दी गई।

पालघर के गांव होंगे किशोरवयीन अनुकूल

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और विशेष रूप से किशोरियों की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन ने एक अहम पहल शुरू की है। संस्था ने अपने प्रेरणा मंच प्रोजेक्ट के तहत किशोरवयीन अनुकूल गांव कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस पहल के तहत सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयासरत गांवों को विशेष नेमप्लेट देकर सम्मानित किया जायेगा।

इस कार्यक्रम को स्थानीय सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, स्कूल प्रशासन व ग्रामसभा का पूर्ण समर्थन मिला है। किशोरियों ने भी इस पहल में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाजी वर्गीस ने कहा कि दुनिया को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए तल्लीन स्तर पर काम करना जरूरी है। यह पहल फिलहाल महाराष्ट्र में शुरू की गई है और जल्द ही अन्य राज्यों में भी लागू की जायेगी।

महाराष्ट्र के पालघर जिले के गांवों ने इस पहल में मॉडल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत डोहरेपाडा और कूर्नझे गांव बालविवाह मुक्त घोषित किये गये हैं। सावरोली गांव ने डिजिटल सुरक्षा और सायबर जागरूकता की दिशा में संकल्प लिया है। साजन गांव ने लड़कियों की स्कूल ड्रॉपआउट दर को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। वांगणी गांव ने महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा-मुक्त वातावरण बनाने की शपथ ली है। रामनगर (कासाटवाड़ी) को व्यसनमुक्त गांव के रूप में घोषित किया गया है। बाल संरक्षण, शिक्षा, लैंगिक समानता, सायबर सुरक्षा और नशा विरोधी जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्रामस्थों द्वारा लिए गये ये निर्णय ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इस पहल के माध्यम से हर बच्चे को सुरक्षित और पोषक वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है।

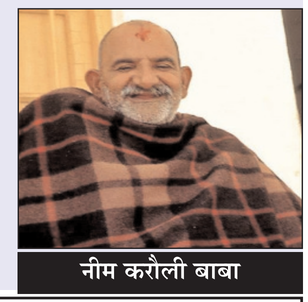

नीम करौली बाबा

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * **संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति,** समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, **मो.-** 9554493941 **email ID- uttarshaktinews@gmail.com**

ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो, महिला समेत दो घायल

जौनपुर के लखौंवां बाजार में हादसा, बाधित रहा यातायात

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बक्सा थाना क्षेत्र के लखौंवां बाजार में गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने-सामने की टक्कर में महिला समेत दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा।

दरअसल, ट्रक लखौंवां मोड़ से मुड़ रही थी। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला तथा चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की

मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लखौंवां मोड़ पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से यहां चेतावनी संकेतक लगाने और वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

बक्सा थाना क्षेत्र के हल्का सिपाही शिव प्रकाश ने बताया कि घायलों की पहचान की जा रही है। दोनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 5 से 21 जून तक चलेगा जनकल्याण एवं जनजागरूकता अभियानः डीएम

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में अभियान की रूपरेखा तय करते हुए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 5 जून से 21 जून 2026 तक जनपद में समेकित जनकल्याण एवं जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सभी कार्यक्रम सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की भावना के अनुरूप आयोजित होंगे। अभियान के दौरान सादगी, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और जनभागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रधानमंत्री के आह्वान पर ₹एक पेड़ मां के नाम₹ अभियान के तहत सभी विकास खंडों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक पौधरोपण किया जाएगा। डीएम ने वन विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेस-वे, नदियों और नहरों के किनारे पौधारोपण कराने तथा सिटी फॉरेस्ट विकसित करने के निर्देश दिए। स्थानीय, पारंपरिक एवं फलदार प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता देने तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित

करने पर जोर दिया गया।

8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित कर सरकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी देंगे। स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण, मलिन बस्तियों में संवाद तथा ₹सरकार आपके द्वार₹ कार्यक्रम के अंतर्गत जनसमस्या समाधान शिविर भी लगाए जाएंगे।

14 से 16 जून तक विकास खंड स्तर पर तीन दिवसीय जनकल्याण मेले एवं स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित होंगे, जिनमें विभिन्न विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण भी करेंगे।

16 से 17 जून तक विकसित भारत संकल्प सम्मेलन तथा 17 से 20 जून तक विकास प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों, आधारभूत संरचना, औद्योगिक परियोजनाओं, आंतरिक सुरक्षा एवं विकसित उत्तर प्रदेश की झलक प्रस्तुत की जाएगी। 18 और 19 जून को प्राकृतिक खेती कार्यशालाओं का आयोजन होगा, जिसमें किसानों को जीवामृत, बीजामृत, प्राकृतिक खाद एवं जैविक कीटनाशक बनाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। गो-आधारित कृषि, जल संरक्षण तथा कम लागत में अधिक आय के विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें युवाओं, महिलाओं, एनसीसी, पुलिस एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साइकिल एवं पैदल जागरूकता यात्राएं भी निकाली जाएंगी।

अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर शासकीय योजनाओं की समीक्षा एवं जन शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी चयनित गांवों में रात्रि विश्राम कर स्थानीय समस्याओं का स्थलीय अध्ययन भी करेंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

डॉक्टर को लॉकअप, थानेदार को 'चाय की सजा'

पीड़ित बोला, अब सड़क या कोर्ट में होगी लड़ाई

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले में एक सम्मानित डेंटल सर्जन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित चिकित्सक ने आरोप लगाया है कि उनके साथ थाने में न केवल अभद्र व्यवहार किया गया, बल्कि शिकायत की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की उम्मीद भी धूमिल हो गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाध्यक्ष को दी गई कथित 'सजा' से उनका दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया है।

डेंटल सर्जन डॉ. प्रभात विक्रम सिंह ने कहा कि अब उन्हें न्याय की उम्मीद प्रशासनिक स्तर पर नहीं दिख रही है, इसलिए वे या तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे या फिर न्यायालय की शरण लेंगे।

डॉ. प्रभात विक्रम सिंह के अनुसार, वह अपनी पैतृक भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण की शिकायत लेकर 25 मई को थाना तेजीबाजार पहुंचे थे। उनका आरोप है कि शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के बजाय तत्कालीन थाना प्रभारी सत्येंद्र भाई पटेल ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया, जूते और बेल्ट उतरवा लिए गए तथा उन्हें घंटों लॉकअप में बैठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बाद में उनका धारा 151 के तहत चालान भी कर दिया गया।

पीड़ित चिकित्सक का कहना है कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी और उन्हें उम्मीद थी कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन, उनके अनुसार पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को केवल इतना कहा कि वह डॉक्टर को थाने बुलाकर उनके साथ चाय पिएं। डॉ. सिंह का आरोप है कि इस कथित फैसले ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम किया है।

उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा शहीद परिवारों को सम्मान देने की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर जौनपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य को थाने में अपमानित किया जाता है। उनका कहना है कि यह केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न नहीं, बल्कि उन परिवारों के सम्मान से भी जुड़ा मुद्दा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया।

मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि यदि एक शिक्षित, प्रतिष्ठित और समाज में सम्मानित चिकित्सक के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लोगों का मानना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा कायम रह सके।

उधर, डॉ. प्रभात विक्रम सिंह ने स्पष्ट कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका कहना है कि सम्मान और न्याय की इस लड़ाई में वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है और लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस विवाद पर आगे क्या कदम उठाता है।

बाबा साहब और कांशीराम के सपनों को साकार करेंगे अखिलेश यादवः अरशद खान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जौनपुर सदर मोहम्मद अरशद खान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सामाजिक न्याय, समान अवसर और संविधान की मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर तथा मान्यवर कांशीराम के सपनों को साकार करने का कार्य कर रहे हैं।

कटघरा स्थित पीडीए भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में अरशद खान ने कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) आंदोलन केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक भागीदारी और संवैधानिक अधिकारों का जनांदोलन है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिलाना है।

उन्होंने कहा कि 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना को मजबूत करते हुए देश में ऐसी

व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में अवसर और भागीदारी प्राप्त हो। ₹जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी₹ सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसी आधार पर शासन-प्रशासन, शिक्षा, रोजगार तथा अन्य संस्थानों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अरशद खान ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसलिए न्यायिक सेवाओं में सामाजिक विविधता और समावेशिता को लेकर गंभीर राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित भारत की परिकल्पना की थी, जबकि कांशीराम ने बहुजन समाज को राजनीतिक चेतना देकर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए आंदोलन सामाजिक न्याय की नई इबारत लिखेगा तथा देश को समान अवसर, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा।

लाइन बाजार पुलिस ने टीजीटी परीक्षा में बायोमैट्रिक रिपोर्ट मिसमैच होने के कारण एक आरोपी को किया गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। टीजीटी परीक्षा, टीडी कालेज जौनपुर में बुधवार को चल रही थी, दौराने चेकिंग आधार कार्ड, बायोमैट्रिक रिपोर्ट मिसमैच होने के कारण आशीष कुमार पुत्र मदन प्रसाद निवासी अद्री इन्दारा जनपद मऊ के स्थान पर राबेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलाल निवासी नगर पंचायत कोराव थाना कोराव जनपद प्रयागराज देते पाये गये, जिनसे विस्तृत पूछताछ की गयी तो बताये कि मैं आशीष कुमार पुत्र मदन प्रसाद निवासी अद्री इन्दारा जनपद मऊ के स्थान पर परीक्षा दे

रहा हूँ, केन्द्र अध्यक्ष प्रो0 कुंवर बहादुर यादव, केन्द्राध्यक्ष तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षा भवन ब्लाक-बी सेन्टर कोड 3605 जौनपुर मो0नं0 7905269295 की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-214/2026 धारा-318(4), 336(2), 336(3), 61(2) बीएनएस व 8/13(4)/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिकपरीक्षा(अनुचित साधनों का निवारण अधि0 2024) पंजीकृत करते हुये आरोपी राबेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलाल निवासी नगर पंचायत कोराव थाना कोराव जनपद प्रयागराज को नियमानुसार गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सुजानगंज थाने का प्याऊ बना शोपीस, प्यास के लिए तरस रहे फरियादी

मछलीशहर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सुजानगंज थाने में पेयजल व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। थाने परिसर में लगाए गए तीनों प्याऊ शोपीस बनकर रह गए हैं, जिससे यहां आने वाले फरियादियों और आम नागरिकों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। क्षेत्र में इन दिनों तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में थाने में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने वाले लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।थाने परिसर में लगे तीनों प्याऊ बंद पड़े हैं और उनमें पानी नहीं आ रहा है। फरियादी गायत्री देवी ने बताया कि वह काफी समय से थाने में बैठी हैं, लेकिन पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं

है। मजबूरन उन्हें बाहर से बोतलबंद पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। वहीं पत्रकार नेहा पटेल ने भी बताया कि थाने में तीन प्याऊ लगे होने के बावजूद किसी में भी पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। थाने में आने वाले लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के इस दौर में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव चिंता का विषय है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से बंद पड़े प्याऊ को शीघ्र चालू कराए जाने तथा पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि फरियादियों और आगंतुकों को राहत मिल सके।

चेयरमैन ने किया पांच करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण

मुंगराबादशाहपुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। स्थानीय नगर के धौरहरा वार्ड में ढाई करोड़ लागत से बने कान्हा गौशाला सहित विभिन्न वार्डों में कराए गए पांच करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण बुधवार सायं राज्य सभा सदस्य सीमा द्विवेदी व नगर पालिका अध्यक्ष ने किया।

धौरहरा वार्ड में ढाई करोड़ रुपए लागत से पांच सौ गौवंश क्षमता का कान्हा गौशाला का लोकार्पण विधि विधान से बतौर मुख्य अतिथि राज्य सभा सदस्य सीमा द्विवेदी व नगर पालिका अध्यक्ष कपिल मुनि ने गौमाता का पूजन कर किया गया। उसके बाद जौनपुर रोड पर दोनों तरफ बनाएं गए जल निकासी नाले सहित आठ नालों का फीता काट कर लोकार्पण किया।इस अवसर पर संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी ने कहा गौमाता की सेवा हमारी सनातन परंपरा है शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता की पीड़ा ईश्वर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं।मैं धन्यवाद देती हूं चेयरमैन सभासद गण एवं अधिशासी अधिकारी को जिन्होंने सराहनीय प्रयास कर इतना

भव्य कान्हा गौशाला बनवाया जहां बेसहारा गौवंश को आश्रय मिलेगा। चेयरमैन कपिल मुनि ने कहा गौवंश संरक्षण प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है।हम प्रत्येक शुभ अवसरों पर गौमाता का पूजन करते हैं यह हमारी परंपरा है।इस कान्हा गौशाला में पांच सौ से अधिक गौवंश को आश्रय मिलेगा। सभासदों से अपील करते हुए कहा कि नगर में हो रहे विकास कार्यों में सहयोग करें हमारा उद्देश्य कि हमारी नगर पालिका जनपद में नहीं प्रदेश में अपनी अलग पहचान कायम करे। इस अवसर पर वार्ड के वयोवृद्ध संभ्रांत जनों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी, मनोज द्विवेदी,राम अक्षैवर पांडेय, प्रमोद दूबे, बृजेश पांडेय, एजाज अहमद, राजेश गुप्ता, रायबरेली मिश्र, चंद्र शेखर पांडेय सभासद गण सहित भारी संख्या में नगर के लोग उपस्थित रहे।

सिंगरामऊ में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, तीन छप्पर जलकर राख

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के करनपुर गांव में गुरुवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने पाल बस्ती में अफरा-तफरी मचा दी। आग की चपेट में आने से तीन छप्पर जलकर पूरी तरह राख हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पाल बस्ती में अचानक बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी निकली, जिसने देखते ही देखते पास के छप्परों को अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सिंगरामऊ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग से तीन छप्परों के जलने के कारण गृहस्थी का सामान भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। समाचार लिखे जाने तक नुकसान का आकलन किया जा रहा था।

बोलेरो ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो चालक समेत पांच घायल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बरसठी थाना क्षेत्र के मौहरी गांव निवासी मुन्ना अपनी तीन बेटियों के साथ गोपालापुर अपने ससुराल गए थे घर वापस आते समय बरसठी थाना क्षेत्र के भान्नौर गांव के पास के सामने से आ रही बोलेरो ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी जिसमें ऑटो पलट गई पलट के क्षतिग्रस्त हो गया ऑटो में बैठे चालक समेत पांच घायल हो गए घायलों में आटो चालक बृजभान 28 वर्ष पुत्र हीरालाल निवासी जमालपुर थाना रामपुर मुन्ना 45 वर्ष खुशबू 12 वर्ष अंजलि 13 वर्ष चांदनी 15 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए 108 द्वारा सभी को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है पुलिस कार्रवाई में जुटी है।

शव लेकर जा रही एम्बुलेंस की स्कॉर्पियो से भिड़ंत, चार घायल

◆ गुरैनी पेट्रोल पंप के पास मचा हड़कंप

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार को एक एम्बुलेंस और स्कॉर्पियो के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो

गई। हादसे के समय एम्बुलेंस में एक महिला का शव लेकर परिजन घर जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में सवार चार लोग घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, एम्बुलेंस में सवार शिवमूर्ति सिंह (75 वर्ष) पुत्र रामसूरत सिंह एवं उनके पुत्र राकेश सिंह, निवासी कराऊपुर थाना अकबरपुर, जनपद अंबेडकरनगर, अपनी पत्नी/माता का शव कोलकाता से लेकर घर लौट रहे थे। गुरैनी पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही सामने से आ रही स्कॉर्पियो से उनकी एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। वहीं स्कॉर्पियो में सवार गिरधारी लाल यादव (61 वर्ष) एवं बेचन राम (63 वर्ष), निवासी उदकरनपुर थाना औराई, जनपद भदोही, अयोध्या से दवा लेकर अपने घर लौट रहे थे। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और सभी चारों लोग घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। हालांकि घटना के संबंध में आधिकारिक जानकारी लेने के लिए खेतासराय थाने के सीयूजी नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो सकी।

29 साल बाद मिला इंसाफः हिरासत में मौत के मामले में पूर्व दरोगा समेत तीन दोषियों को सजा

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। लगभग तीन दशक पुराने पुलिस हिरासत मृत्यु मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारी, विवेचक और पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को दोषी ठहराकर सजा सुनाई है। यह फैसला उस लंबे कानूनी संघर्ष का परिणाम है, जिसे मृतक राजेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी शशिमा सिंह ने 29 वर्षों तक लगातार जारी रखा।

अदालत ने मामले में तत्कालीन दरोगा नरेंद्र प्रताप सिंह को 10 वर्ष के कारावास, विवेचक राधेश्याम सिंह को छह महीने की सजा तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. के.के. जैन को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 1997 में सुंदरपुर पुलिस चौकी में हुई एक संदिग्ध मौत से जुड़ा था, जिसे शुरूआती दौर में पुलिस ने आत्महत्या करार दे दिया था।

100 मिनट में गढ़ दी गई आत्महत्या की कहानीः जांच के दौरान सामने आया कि पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को शाम 5:15 बजे अपनी अभिरक्षा में दर्शाया था। इसके महज 100 मिनट बाद, शाम 6:55 बजे यह दावा कर दिया गया कि उन्होंने लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि बाद में हुई जांच में पुलिस की इस कहानी पर गंभीर सवाल खड़े हुए।

सीबीसीआईडी की जांच में पाया गया कि राजेंद्र को वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में रखा गया था। गिरफ्तारी से जुड़े आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। इतना ही नहीं, परिजनों को सूचना दिए बिना अगले दिन भोर में पोस्टमार्टम कराकर शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया।

चोरी का मुकदमा भी निकला संदिग्धः राजेंद्र प्रसाद सिंह को जिस कथित चोरी के मामले में पुलिस चौकी लाया गया था, वह भी जांच में संदेह के घेरे में आ गया। पुलिस ने उनकी मौत के बाद 100 रुपये की चोरी का मुकदमा दर्ज किया था।

इस प्राथमिकी के आधार बने शिकायतकर्ता दयाराम के पते की जब जांच हुई तो वह फर्जी पाया गया। जांच एजेंसियों ने मिजार्पुर जिले के विभिन्न गांवों में सत्यापन कराया, लेकिन उस नाम और पते का कोई व्यक्ति नहीं मिला। स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम प्रधानों और मतदाता सूची के रिकॉर्ड से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई कि मुकदमे का कथित शिकायतकर्ता वास्तविक नहीं था।

पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेण्डर्स को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जनपद में 01 जून सोमवार से एक माह का विशेष अभियान शुरू हो गया है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत तीन अलग-अलग स्तरों पर चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्वनिधि महोत्सव आयोजित होगा।

इसमें स्ट्रीट वेण्डर्स और उनके परिवारों की सफलता की कहानियों व उपलब्धियों का उत्सव मनाया जायेगा ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सके। इसके अलावा नगर निकाय स्तर पर लोक कल्याण मेले आयोजित किये जायेंगे और बैंकर्स और स्ट्रीट वेण्डर्स की बैठकें होंगी। वेण्डर्स को ऋण व क्रेडिट कार्ड की सुविधा, डिजिटल सशक्तिकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मौके पर ही जोड़ा जायेगा।

उक्त जानकारी देते हुए परियोजना अधिकारी डूडा निधि बाजपेयी ने बताया कि सभी नगर निकायों के साथ-साथ सेंन्सेस टाउन स्तर पर भी स्वनिधि कैंप लगाये जायेंगे। इन कैम्पों में नये स्ट्रीट वेण्डर्स की पहचान कर उन्हें योजना में शामिल किया जायेगा। इस अभियान के तहत स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम ऋण प्राप्त वेण्डर्स और उनके परिवारों की प्रोफाइलिंग कर उन्हें सीधे 08 सरकारी योजनाओं यथा-पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम जनधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृ वन्दना योजना, श्रम विभाग में पंजीकरण का लाभ दिलाया जायेगा। परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि जो वेण्डर्स दूसरा व तीसरा ऋण प्राप्त चुके हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कराया जायेगा और जिन्हें कार्ड मिल चुका है, उन्हें उसके सही इस्तेमाल की ट्रेनिंग बैंक द्वारा दी जायेगी। सेन्सेस टाउन महिमापुर के ठेला-खोमचा कारोबारियों को भी मिलेगा बिना गारण्टी के ऋण।

पीएम स्वनिधि योजना का हुआ विस्तार-छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत सेन्सेट टाउन के रूप में जलालपुर विकास खण्ड के चयनित ग्राम पंचायत महिमापुर के ठेला-खोमचा कारोबारियों को भी अब बिना गारण्टी के प्रथम ऋण के रूप में पन्द्रह हजार रुपए ऋण बैंकों द्वारा दिया जायेगा। शासन द्वारा केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा बढ़ाते हुए उक्त ग्राम महिमापुर विकास खण्ड जलालपुर को सेन्सेस टाउन के रूप में चयनित कर इस गांव के रेहड़ी-पटरी के दुकानदारों को इस योजना से जोड़ा गया है। सेन्सेस टाउन महिमापुर का नोडल अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी जलालपुर जौनपुर को बनाया गया है। अब तक यह योजना मुख्य रूप से नगरीय निकाय क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इस योजना से छोटे दुकानदारों को काफी राहत मिलेगी। जो सीमित पूॅजी के कारण अपना व्यवसाय बढ़ाने में असमर्थ थे अथवा कठिनाईयों का सामना कर रहे थे, अब उन्हें बिना किसी गारण्टी के बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वे अपनी दुकान के लिए सामान खरीद कर अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उक्त जानकारी जितेन्द्र सिंह, शहर मिशन प्रबन्धक डूडा जौनपुर ने दी।

इंदौर नगर निगम के सिर्फ कागजों पर बने ड्रेनेज-सीवरेज प्रोजेक्टः ईडी कसा शिकंजा

-प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तरशक्ति)। इंदौर नगर निगम में 92 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में एऊ ने शिकंजा कसा जिसमें पूर्व इंजीनियर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर नगर निगम के चर्चित फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड निगम के पूर्व सहायक यंत्री अभय सिंह राठौर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद जाकिर और राहुल वडेरा शामील है। तीनों आरोपीयों को पकड़ कर एऊपूछताछ कर रही है। विशेष सुत्रों के हवाले से पता चला कि अभी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसने वाली है।जांच में सामने आया है कि घोटाले को अंजाम देने के लिए पुराने और पूर्ण हो चुके कार्यों को नया दर्शाकर फर्जी वर्क ऑर्डर और भुगतान फाइलें तैयार की गईं। आरोपियों ने अधिकारियों के लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सिस्टम एक्सेस का दुरुपयोग करते हुए फर्जी बिलों को लेखा शाखा तक पहुंचाया और भुगतान भी करवा लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार बिना कार्य किए तकनीकी स्वीकृति, ऑडिट और भुगतान की पूरी प्रक्रिया कागजों में पूरी कर दी गई थी। इसके बाद करोड़ों रुपये ठेकेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।

बनारस में दो युवकों के शव मिलने से हड़कंप, जमीन के सिलसिले में घर से निकले थे

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र स्थित हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के पीछे गुरुवार सुबह दो युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े इन शवों पर जब कॉलेज के स्टाफ की नजर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. खबर मिलते ही ऊब्ढ, अउढ चोलापुर थाने की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई है। इधर दो शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, मामला बनियापुर इलाके का है, जहां गुरुवार की सुबह दो लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े मिले। खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं, सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से जहरीला पदार्थ और खराब की बोतलें भी मिली हैं, जिससे मामले को लेकर कई तरह की आशंका जताई जा रही है।

प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान नई बस्ती हुकुलगंज निवासी अभिजीत गांगुली (47) और कोहासी चोलापुर निवासी निहाल सिंह (40) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जमीन के कारोबार से जुड़े थे और किसी रिश्तेदार की जमीन देखने गए थे, लेकिन उनसे साथ क्या हुआ, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है।

मृतक अभिजीत गांगुली के भाई की पत्नी ने बताया कि अभिजीत बीते 1 अप्रैल से चोलापुर में निहाल सिंह के साथ रह रहे थे। वे दोनों अत्यधिक शराब पीने के आदी थे और अक्सर आपस में मारपीट भी करते थे। आशंका है कि घटना वाले दिन भी दोनों ने शराब के नशे में आपस में मारपीट की होगी और फिर जहर खा लिया होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो जहर नहीं खा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि किसी ने जहर देकर इनकी हत्या की हो। खबर मिलते ही मौके पर डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना, एसओ चोलापुर और एसओजी टीम पहुंची है. फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। वरुणा जोन के डीसीपी डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि शव पुराने प्रतीत हो रहे हैं और उनसे दुर्गंध आ रही थी। घर वालों ने बताया कि दोनों यहां अकेले रहते थे। दोनों के पास से सल्फास के पैकेट मिले हैं, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। अभिजीत की बुधवार सुबह मां से बात हुई थी।उसके बाद किसी से संपर्क में नहीं हुआ। डीसीपी ने कहा कि फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट के बाद ही कोई बात कही जा सकती है।पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

स्टाइल, परफॉर्मेंस और एआई का संगम

गयाजी। मोटोरोला ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस लॉन्च किया। यह स्मार्टफोन प्रो-ग्रेड फोटोग्राफी, प्रीमियम डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और एडवांस्ड एआई फीचर्स के साथ पेश किया गया है। फोन में क्वाड 50 एमपी प्रो-ग्रेड कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें 50 एमपी सोनी लिटिया 710 मुख्य कैमरा, 50 एमपी 3.5एक्स पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, 50 एमपी अल्ट्रा-वाइड प्लस मैक्रो विजन कैमरा और 50 एमपी ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा शामिल हैं।

आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपर्सने माहिम में 800 करोड़ GDV वाले प्रोजेक्ट के लिए एक प्रमुख जमीन के विकास अधिकार हासिल किए हैं

मुंबई। दक्षिण-मध्य मुंबई की एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर, सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड ने अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आइकॉनिक प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, माहिम (पश्चिम) में स्थित हमारे चल रहे कमर्शियल प्रोजेक्ट 'सूरज वन बिजनेस बे' से सटी हुई लगभग 2,941 वर्ग मीटर की जमीन के विकास अधिकार हासिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा कुल 75.00 करोड़ में हुआ है। माहिम मुंबई के स्थापित माइक्रो-मार्केट में से एक है, जिसकी पहचान मजबूत मांग, बेहतरीन कनेक्टिविटी और लोअर परेल, वर्ली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे प्रमुख कमर्शियल ज़िलों से निकटता के कारण होती है। मौजूदा कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ इस जमीन को मिलाने पर, लगभग 1.50 लाख वर्ग फुट का अतिरिक्त बिक्री योग्य कारपेट एरिया मिलने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित GDV 800 करोड़ होगा। इस प्रोजेक्ट से कंपनी की निकट-से-मध्यम अवधि की प्रोजेक्ट पाइपलाइन को मजबूती मिलने और दक्षिण-मध्य मुंबई के अपने मुख्य बाजार में उसकी उपस्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। इस अपडेट पर टिप्पणी करते हुए, सूरज एस्टेट डेवलपर्स के पूर्णकालिक निदेशक, राहुल थॉमस ने कहा, ॅयह अधिग्रहण, जो चल रहे 'सूरज वन बिजनेस बे' से सटा हुआ है, दक्षिण-मध्य मुंबई में कंपनी के कमर्शियल विस्तार को बढ़ाएगा।

आईएचजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स ने इंटरकॉन्टिनेंटल मुंबई गोरेगांव होटल की घोषणा की

मुंबई। दुनिया की प्रमुख हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक आईएचजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स ने जोन होटल्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट साइन करने की घोषणा की है। इस समझौते के तहत मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल मुंबई गोरेगांव होटल विकसित किया जाएगा। इस होटल के 2030 की पहली तिमाही (Q1 2030) में शुरू होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट भारत में आईएचजी के लग्जरी होटल पोर्टफोलियो और मजबूत करेगा और मुंबई जैसे प्रमुख बिजनेस और पर्यटन बाजार में कंपनी की मौजूदगी को बढ़ाएगा।

मुंबई के तेजी से विकसित हो रहे पश्चिमी उपनगरों में से एक गोरेगांव में यह होटल बनाया जाएगा। इस होटल में कुल 350 लग्जरी गेस्ट कमरे होंगे, जिनमें 70 सुइट्स शामिल होंगे। अंधेरी और मालाड के बीच स्थित होने के कारण इस होटल को शहर के सभी प्रमुख हिस्सों से बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। इसलिए यह होटल बिजनेस और पर्यटन दोनों तरह के यात्रियों के लिए एक बेहतरीन स्थान होगा। इस नए प्रोजेक्ट से मुंबई में आईएचजी के लग्जरी होटलों की संख्या बढ़ेगी और भारत के तेजी से बढ़ते हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में विस्तार की कंपनी की विस्तार योजना को और मजबूती मिलेगी। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय लग्जरी होटल ब्रांड है, जो नए स्थानों की खोज, विभिन्न संस्कृतियों के अनुभव और वैश्विक यात्रा अनुभवों के लिए जाना जाता है। फिलहाल इस ब्रांड के दुनिया भर में 237 से अधिक होटल चल रहे हैं और 100 से ज्यादा होटल निर्माण की प्रक्रिया में हैं। बड़े शहरों के प्रसिद्ध स्थानों से लेकर आरामदायक रिसॉर्ट्स तक, यह ब्रांड लगातार नए-नए स्थानों पर अपने होटल का विस्तार कर रहा है। इसके के हर होटल का उद्देश्य मेहमानों को स्थानीय संस्कृति और अनुभवों से जोड़ना और एक खास यात्रा अनुभव देना होता है। इस समझौते के बारे में बात करते हुए आईएचजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के साउथ वेस्ट एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप जैन ने कहा, हम मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल मुंबई गोरेगांव होटल लाने के लिए जोन होटल्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हैं। मुंबई में व्यापार और पर्यटन दोनों तरह की यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है। साथ ही, गोरेगांव एक तेजी से विकसित होता व्यावसायिक केंद्र बन रहा है, इसलिए यह हमारे लग्जरी होटलों के विस्तार के लिए एक बहुत उपयुक्त स्थान है। संदीप गुप्ता, डायरेक्टर, जोन होटल्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड ने कहा, ॅगोरेगांव में दुनिया भर में प्रसिद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल ब्रांड लाने के लिए आईएचजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के साथ साझेदारी करके हमें बहुत खुशी हो रही है।

NEET-JEE में सफलता के लिए सही दिशा जरूरी : तिवारी सरस्वती क्लासेज

प्रेम चंद मिश्रा

मुंबई - (उत्तर शक्ति) मुंबई सहित महाराष्ट्र में विज्ञान शिक्षा के बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में तिवारी सरस्वती क्लासेज विद्यार्थियों के लिए एक भरोसेमंद संस्थान बनकर उभरा है। संस्थान के डायरेक्टर डॉ. दयानंद तिवारी के नेतृत्व में यहां कॉन्सेप्ट आधारित शिक्षण, नियमित टेस्ट और व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संस्थान से अब तक 500 से अधिक डॉक्टर और 3000 इंजीनियर तैयार हो चुके हैं, वहीं 200 से अधिक विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2025 में 17 छात्र डॉक्टर और 67 इंजीनियर बने। NEET, JEE और MHT-CET 2025 में भी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

वरिष्ठ समाजसेवी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक के डी शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार लाल शेखर सिंह को दिया स्नेह पूर्ण आशीर्वाद

वसई (उत्तरशक्ति)। वरिष्ठ समाजसेवी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक के डी शर्मा जो कि सभी लोगों में बहुत ही प्रिय बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े नेताओं में विशिष्ट स्थान रखने वाले ब्राह्मण समाज के प्रथम पंक्ति के नेता व उत्तर भारतीय समाज के जन प्रिय है,समय समय पर समाज के लोगों का मनोबल और उनके द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्यों के लिए प्रशंसा और मनोबल बढाते रहते है इसी कड़ी में उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार लालशेखर सिंह के लिए अपना आशीष दिया है,उनके ही शब्दों में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाल शेखर सिंह जी एक सम्मानित, सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी लेखनी केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि समाज की संवेदनाओं, विचारों और वास्तविकताओं का सशक्त प्रतिबिंब है। आपकी स्पष्ट सोच, निष्पक्ष दृष्टिकोण, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विषयों की गहरी समझ तथा उच्च बौद्धिक स्तर वास्तव में प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। आपकी कलम सदैव सत्य, न्याय और जनहित की आवाज बनकर समाज को दिशा देती रहे। आपके व्यक्तित्व की गरिमा और आपकी विचारशीलता निरंतर नई ऊँचाइयों को स्पर्श करे, यही हार्दिक शुभकामना है।

दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट

मुंबई। एक रात, एक रहस्यमयी घटना ओक स्ट्रीट को उसकी दुनिया से छीनकर किसी अनजान और डरावनी जगह पर ले जाती है।। प्लैट परिवार को जल्द ही एहसास होता है कि इस भयानक और पूरी तरह बदल चुकी जगह में जिंदा रहने का एक ही रास्ता है- हर हाल में एक-दूसरे का साथ निभाना। ऐन हैथवे और ईवान मैकग्रेगर अभिनीत ॅदी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट में मैसी स्टेला और क्रिश्चिपन कॉनवे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के लेखक और निर्देशक डेविड रॉबर्ट मिचेल हैं। इसके निमार्ता हैं जे.जे. अब्राम्स, हन्ना मिंगडेला, जॉन कोहेन, डेविड रॉबर्ट मिचेल, मैट जैक्सन और टॉमी हार्पर। वहीं क्रिस बेंडर, जेक वाइनर, जोएन ली और लौएन स्टोनब्रेकर्स फिल्म के कार्यकारी निमार्ता हैं। कैमरे के पीछे डेविड रॉबर्ट मिचेल की टीम में छायांकन निर्देशक माइकल जियोलाकिस, प्रोडक्शन डिजाइनर माया शिमोगुची, संपादक जॉन एक्सलरेंड, संगीतकार माइकल जियाकिनो और कॉस्ट्यूम डिजाइनर एरिन बेनैक शामिल हैं। वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स प्रस्तुत, बैड रोबोट प्रोडक्शन, जैक्सन पिक्चर्स प्रोडक्शन और डेविड रॉबर्ट मिचेल की फिल्म ॅदी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट अगस्त २०२६ में भारत में केवल सिनेमाघरों और आई मैक्स में रिलीज होगी।

सेन्सेस टाउन महिमापुर के ठेला-खोमचा कारोबारियों को भी मिलेगा बिना गारण्टी के ऋण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पीएम स्वनिधि योजना का हुआ विस्तार - छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत सेन्सेट टाउन के रूप में जलालपुर विकास खण्ड के चयनित ग्राम पंचायत महिमापुर के ठेला-खोमचा कारोबारियों को भी अब बिना गारण्टी के प्रथम ऋण के रूप में पन्द्रह हजार रुपए ऋण बैंकों द्वारा दिया जायेगा। शासन द्वारा केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा बढ़ाते हुए उक्त ग्राम महिमापुर विकास खण्ड जलालपुर को सेन्सेस टाउन के रूप में चयनित कर इस गांव के रेहड़ी-पटरी के दुकानदारों को इस योजना से जोड़ा गया है। सेन्सेस टाउन महिमापुर का नोडल अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी जलालपुर जौनपुर को बनाया गया है। अब तक यह योजना मुख्य रूप से नगरीय निकाय क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इस योजना से छोटे दुकानदारों को काफी राहत मिलेगी। जो सीमित पूँजी के कारण अपना व्यवसाय बढ़ाने में असमर्थ थे अथवा कठिनाईयों का सामना कर रहे थे, अब उन्हें बिना किसी गारण्टी के बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे वे अपनी दुकान के लिए सामान खरीद कर अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उक्त जानकारी जितेन्द्र सिंह, शहर मिशन प्रबन्धक डूडा जौनपुर ने दी।

सेन्सेस टाउन महिमापुर के ठेला-खोमचा कारोबारियों को भी मिलेगा बिना गारण्टी के ऋण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। पीएम स्वनिधि योजना का हुआ विस्तार - छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत सेन्सेट टाउन के रूप में जलालपुर विकास खण्ड के चयनित ग्राम पंचायत महिमापुर के ठेला-खोमचा कारोबारियों को भी अब बिना गारण्टी के प्रथम ऋण के रूप में पन्द्रह हजार रुपए ऋण बैंकों द्वारा दिया जायेगा। शासन द्वारा केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा बढ़ाते हुए उक्त ग्राम महिमापुर विकास खण्ड जलालपुर को सेन्सेस टाउन के रूप में चयनित कर इस गांव के रेहड़ी-पटरी के दुकानदारों को इस योजना से जोड़ा गया है। सेन्सेस टाउन महिमापुर का नोडल अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी जलालपुर जौनपुर को बनाया गया है।

राइस एडमास समूह ने मुंबई कार्यालय का उद्घाटन किया, मानव संसाधन नेतृत्व सम्मेलन 2026 का आयोजन

मुंबई। राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राइस एडमास समूह के अंतर्गत आने वाले एडमास विश्वविद्यालय और एडमास टेक कंसल्टिंग ने अंधेरी पूर्व स्थित कनाकिया वॉल स्ट्रीट में अपने नए मुंबई कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय एडमास अनुभवात्मक शिक्षण विद्यालय के बैनर तले स्थापित किया गया है। एडमास अनुभवात्मक शिक्षण विद्यालय एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को पश्चिम बंगाल की सीमाओं से बाहर निकालकर भारत के प्रमुख आर्थिक और नवाचार केंद्रों से जोड़ना है। इस पहल के तहत दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद सहित छह प्रमुख शहरों में 10-दिवसीय आवासीय शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को वास्तविक औद्योगिक अनुभव, व्यावसायिक आत्मविश्वास तथा देशव्यापी दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर मिलेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिह्नित करने के लिए समूह ने मुंबई क्रिकेट संघ केंद्र में मानव संसाधन नेतृत्व सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू हुआ और परिचयात्मक संवाद एवं रात्रिभोज के साथ संपन्न हुआ। प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन की पुनर्कल्पना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में 80 से अधिक प्रतिष्ठित उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया, जिनमें प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, मानव संसाधन व्यवसाय सहयोगी और विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ पेशेवर शामिल थे। सम्मेलन में कुलाधिपति प्रो. (डॉ.) समित रे ने उद्योग और शिक्षा जगत के बीच साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि भविष्य के लिए तैयार, नवाचारी और नेतृत्व क्षमता से युक्त पेशेवर तैयार किए जा सकें। कार्यक्रम में राइस एडमास समूह के समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऊमन थॉमस की उपस्थिति ने संस्थान की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक दृष्टि को और मजबूती प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन प्रो. अभिजीत गिरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष झ करियर विकास केंद्र एवं परामर्श तथा समूह जनसंपर्क, कौशल एवं परामर्श, एडमास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया।

विरोहन की बड़ी पहल, महिलाओं के लिए 2 करोड़ की स्कॉलरशिप से खुलेगा हेल्थकेयर करियर का रास्ता

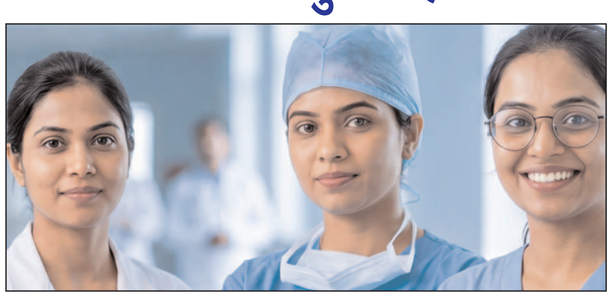

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख हेल्थकेयर एजुकेशन कंपनी विरोहन ने वुमन इन हेल्थकेयर पहल की शुरूआत करते हुए 2 करोड़ की स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य देश के तेजी से बढ़ते हेल्थकेयर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें मजबूत करियर अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र महिला आवेदकों को 50,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, चाहे वे चार से पांच वर्ष के डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लें या एक वर्ष के सर्टिफिकेट कोर्स में। 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 1,00,000 और 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 2,00,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। यह राशि सीधे कोर्स फीस में समायोजित की जाएगी जिससे शिक्षा अधिक सुलभ हो सके। इस पहल पर विरोहन के को-फाउंडर और सीटीओ नलिन सलूजा ने प्रतिक्रिया ने देते हुए कहा, हेल्थकेयर सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जो सम्मान, स्थिरता और उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और इसमें महिलाओं की भूमिका हमेशा से बेहद अहम रही है। वुमन इन हेल्थकेयर पहल इसी सोच पर आधारित है कि अधिक से अधिक महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। आज दुनिया गंभीर रूप से हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की कमी का सामना कर रही है, और भारत के पास इस बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता है, चाहे देश में हो या वैश्विक स्तर पर। हमारी समझ में सबसे बड़ी चुनौती जागरूकता की कमी है। छात्राओं को यह पता नहीं है कि एलाइड और हेल्थकेयर में कितने करियर विकल्प मौजूद हैं, और अभिभावकों को भी इन भूमिकाओं की मांग और करियर ग्रोथ को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह स्कॉलरशिप इस बात का संकेत है कि अवसर वास्तविक हैं, विश्वविद्यालय तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि अधिक महिलाएं इस अवसर का लाभ उठाएं।

विरोहन के माध्यम से छात्राएं यूपीईएस (देहरादून), एमआईटी यूनिवर्सिटी (शिलांग), सीएमआर यूनिवर्सिटी (बेंगलुरु), केआईईटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (गाजियाबाद), एचआरआईटी यूनिवर्सिटी (गाजियाबाद), लिंगायाज विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (फरीदाबाद), सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी (अहमदाबाद) और विक्रांत यूनिवर्सिटी (ग्वालियर) सहित कई अन्य संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं। यह कदम महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा शिक्षा को व्यापक बनाने की विरोहन की दूरदर्शी सोच का प्रमाण है।

फूल दोगे तो फूल ही मिलेगा, पत्थर दोगे तो पत्थर ही मिलेगा, इसलिए कोई आलोचना करे तो शांत रहना चाहिए

मुंबई। खानापुर-आटपाडी के विधायक सुहास बाबर एक पीपल के पेड़ की तरह जोश से भरे हुए हैं। उस जोश को बढ़ाने, संवारने और उसे सींचने की जिम्मेदारी हम सबकी है, ऐसे भावपूर्ण शब्दों में वरिष्ठ अभिनेता जैकी श्रॉफ ने शिवसेना के विधायक सुहास बाबर के कार्यों की सराहना करते हुए ट्री आर्मी की वृक्षारोपण मुहिम को मजबूती से समर्थन दिया। गार्डी-घानवड के मैदान में ट्री आर्मी और जेके फाउंडेशन के माध्यम से साढ़े चार हजार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर जैकी श्रॉफ के हाथों इस जनआंदोलन का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जैकी श्रॉफ ने विधायक बाबर की सादगी, कार्य के प्रति समर्पण और पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा, सिर्फ बोलने वाले और वास्तव में काम करने वाले लोगों में फर्क होता है। सुहास बाबर जितना बोलते हैं, उतनी ही ईमानदारी से काम भी करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने वृक्षारोपण के माध्यम से समाज को दिशा देने वाले इस अभियान की सराहना की और यह संदेश दिया कि पृथ्वी हमारी मां है, उसकी रक्षा के लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए। विधायक सुहास बाबर ने कहा कि ट्री आर्मी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पूरे समाज की मुहिम है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में मिले मतों की संख्या के बराबर पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है और अगले दो वर्षों में 78 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जैकी श्रॉफ के जुड़ने से इस अभियान को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और विटा से शुरू हुई ट्री आर्मी अब देश और दुनिया तक पहुंचेगी, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में मुंबई से जैकी श्रॉफ के मित्र तथा ड्रीम वर्थ सोल्यूशन कंपनी के संचालक भी उपस्थित थे। साथ ही खानापुर पंचायत समिति की सभापति सुवर्णा भोसले, नगराध्यक्ष काजल म्हेत्रे, उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर, प्रांताधिकारी डॉ. विक्रम बांदल, तहसीलदार योगेश्वर टोम्पे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी विपुल पाटील, गट विकास अधिकारी डॉ. संताजी पाटील, पुलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे, उपसभापति सुहास शिंदे, पूर्व नगरसेवक अमर शितोळे, नविन यात्रा समिति के अध्यक्ष रणजित पाटील, खरीद-विक्री संघ के चेयरमैन हेमंत बाबर, प्रकाश बागल, नगरसेवक रामचंद्र भिंगारदेवे, भालचंद्र कांबळे, रोहित पाटील, एडवोकेट रोहित पवार, श्रीधर जाधव, सरपंच संग्राम नलवडे, सौरभ रोकडे, विशाल पाटील, दिलीप किर्दत, सुजय गोसावी सहित ट्री आर्मी के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस कार्यक्रम की स्वागत एवं प्रस्तावना फिरोज शेख ने की, संचालन धीरज भिंगारदेवे ने किया और आभार राहुल सालुंखे ने व्यक्त किया।

पीएनबी ने पीएनबी हरित निवास ग्रीन होम लोन योजना के माध्यम से स्थायी आवास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया

मुंबई। सतत वित्तपोषण और पर्यावरण के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बैंकिंग की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, पंजाब नैशनल बैंक ने अपनी पीएनबी हरित निवास ग्रीन होम लोन योजना को सशक्त बनाया है। इस पहल का उद्देश्य स्थायी आवास को बढ़ावा देना और घर खरीदारों व मकान मालिकों को अधिक हरित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली को आत्मसात करने हेतु प्रोत्साहित करना है। पीएनबी हरित निवास को ग्राहकों के एक विस्तृत वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें वेतनभोगी व्यक्ति, पेशेवर, स्वरोजगार व्यक्ति, पेंशनभोगी, व्यवसायी और किसान शामिल हैं। यह योजना पहले से तैयार ग्रीन होम, स्वीकृत परियोजनाओं में निमार्णाधीन संपत्तियों, अपने भूखंडों पर स्व-निर्माण के साथ-साथ मौजूदा घरों को ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप अनुकूलित करने के लिए उनके नवीकरण और आधुनिकीकरण को कवर करती है। पीएनबी हरित निवास के माध्यम से बैंक मान्यता प्राप्त ग्रीन बिल्डिंग फ्रेमवर्क के तहत प्रमाणित आवासीय संपत्तियों के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करता है। इसके माध्यम से बैंक उन ग्राहकों की सहायता करता है जो पर्यावरण के अनुकूलऔर स्थायी घर खरीदना, बनाना या उन्हें अपग्रेड करना चाहते हैं। पीएनबी हरित निवास' योजना के अंतर्गत ग्राहकों को कई विशेष लाभ दिए जा रहे हैं। यह योजना नियमित आय स्रोत वाले वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों, पेशेवरों, स्वरोजगार करने वाले लोगों, व्यवसायियों और नियमित आय वाले किसानों के लिए उपलब्ध है, जिससे विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए स्थायी आवास वित्तपोषण तक पहुंच आसान हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने व्याख्यान में, पीएनबी के रिटेल आस्ति व्यवसाय प्रभाग के महाप्रबंधक सुबोध कुमार ने कहा ॅपंजाब नैशनल बैंक में, स्थिरता हमारी विकास रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। 'पीएनबी हरित निवास' के माध्यम से, हम देश भर के ग्राहकों के लिए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार आवास को अधिक किफायती और सुलभ बना रहे हैं। यह योजना न केवल आकर्षक वित्तीय लाभ प्रदान करती है बल्कि ऊर्जा-कुशल घरों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और घरेलू ऊर्जा लागत को घटाने में योगदान देते हैं।

मौत के मुहाने पर तीर्थनगरियां, सिस्टम को अगली लाशों का इंतजार?

वाराणसी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लूरिश स्टे में लगी आग में 21 लोगों की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का भयावह दस्तावेज है। जांच में सामने आया कि जिस प्रतिष्ठान को महज छह कमरों के बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) संचालन की अनुमति थी, वहां 25 कमरे चलाए जा रहे थे। मालिक को परिसर में रहना था, लेकिन वह मौजूद नहीं था। घरेलू बिजली-पानी के कनेक्शन पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं। फायर एनओसी नहीं थी, आपातकालीन निकास नहीं था और छत तक पहुंचने का रास्ता भी बंद था। यह सब प्रशासनिक एजेंसियों की आंखों के सामने होता रहा और आखिरकार 21 लोग जिंदा जल गए। दिल्ली की यह त्रासदी अब केवल राजधानी की कहानी नहीं रह गई है। यह वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार जैसे उन धार्मिक नगरों के लिए भी चेतावनी है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। खास यह है कि हादसे के बाद जांच होती है, हर बार दोषी पकड़े जाते हैं, हर बार सुधार के दावे होते हैं। फिर भी आग लौट आती है। आखिर कब तक लाशें गिनकर जागेगा सिस्टम?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 से पहले दिल्ली में कमरों की कमी को देखते हुए 2007 में बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) नीति लागू की गई थी। मकसद था कि लोग अपने घरों के कुछ कमरे पर्यटकों को किराये पर दें। नियम स्पष्ट थे–मालिक उसी मकान में रहेगा, अधिकतम छह कमरे ही किराये पर दिए जा सकेंगे और कुल कमरों के दो-तिहाई से अधिक हिस्से का व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा। 2008 में नियम और कड़े किए गए ताकि केवल वास्तविक मालिक ही इस योजना का लाभ उठा सकें। 2025 तक दिल्ली पुलिस की अनुमति और सत्यापन भी अनिवार्य था। पुलिस न केवल दस्तावेजों की जांच करती थी बल्कि भौतिक सत्यापन भी करती थी। उद्देश्य यह था कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या फर्जी संचालक इस व्यवस्था का दुरुपयोग न कर सके। लेकिन समय के साथ निगरानी ढीली पड़ती गई और कई स्थानों पर बी एंड बी व्यवस्था छोटे होटलों में बदलती चली गई। दिल्ली का ताजा हादसा इसी विफल निगरानी का परिणाम माना जा रहा है। महाकुंभ के बाद काशी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी। होटल क्षमता कम पड़ने लगी तो पेइंग गेस्ट हाउसों को प्रोत्साहन मिला। आज गोदौलिया, दशाश्वमेध, सोनारपुरा, अस्सी, लंका, शिवाला, नगवा, रविंद्रपुरी और काशी विश्वनाथ धाम के आसपास बड़ी संख्या में मकानों को पर्यटक आवास में बदला जा चुका है। सैकड़ों पेइंग गेस्ट हाउस पंजीकृत हैं और बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जो विभिन्न श्रेणियों में संचालित हो रहे हैं। सवाल यह नहीं कि वे वैध हैं या अवैध, बल्कि यह है कि क्या सभी स्थानों पर सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है? काशी की गलियों में आधी रात को आग लगी तो क्या होगा? यह सवाल अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

एचडीएफसी बैंक के परिवर्तन ने पराली जलाने पर लगाई रोक

पटना। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एचडीएफसी बैंक ने अपने सीएसआर कार्यक्रम ह्यपरिवर्तनह्ण के तहत सीआईआई फाउंडेशन के सहयोग से संचालित फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा की। वर्ष 2025 में पंजाब और हरियाणा के 3.78 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में से 88 प्रतिशत खेतों को पराली जलाने से बचाया गया। यह कार्यक्रम पंजाब के लुधियाना और संगरूर तथा हरियाणा के फतेहाबाद जिले के 380 से अधिक गांवों के करीब 86,000 किसानों तक पहुंचा। पहल के तहत 450 से अधिक कृषि मशीनें किसान सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को उपलब्ध कराई गईं, जिससे किसानों को पराली प्रबंधन के लिए किफायती समाधान मिला। कार्यक्रम के तहत अब तक 8 गांव पूरी तरह पराली मुक्त बने हैं, जबकि 174 गांवों में 90 प्रतिशत से अधिक किसानों ने पराली न जलाने की पद्धति अपनाई है।